✳Website : www.kalamlok.com✳

वर्ष - 09 अंक - 335

बक्सर, रविवार 19 अप्रैल 2026

< 7 |

कलम लोक

पृष्ठ - 8
मूल्य 2 रू.

> सत्य बोलते समय हमारे शरीर पर कोई दबाव नहीं पड़ता, लेकिन झूठ बोलने पर हमारे शरीर पर अनेक प्रकार का दबाव पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि सत्य के लिये एक हाँ और झूठ के लिये हज़ारों बहाने ढूँढने पड़ते हैं।

खुशी से तालियां बजा रहे थे, महिलाओं से अधिकार छीनकर मेज थपथपा रहे थे; पीएम का विपक्ष पर निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह लोग बिल गिरने के बाद मेजें थपथपा रहे थे। यह टेबल पर थाप नहीं थी, यह नारी के स्वाभिमान आत्मसम्मान पर चोट थी। उन्होंने आगे कहाकि जब इन्हें जनता देखेगी तो कहेगी कि इन्हीं लोगों ने नारी की शक्ति छीनी थी। इन दलों से दो-टूक कहूंगा, यह लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है। जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे।

इससे पहले पीएम मोदी ने कहाकि भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेहरमी से कुचल दिया गया है। उन्होंने कहाकि हमारी भरसक कोशिश के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। जब दल हित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को देशहित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहाकि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।

पीएम मोदी ने खासतौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहाकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला अधिकारों की भ्रूण हत्या कर दी है। उन्होंने कहाकि कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को बचा रही है। उन्होंने कहाकि कांग्रेस ने इतिहास रचने का मौका खो दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी झूठ का सहारा लेती है तो कभी कोई और तरीका अपनाकर देश को गुमराह किया है। उन्होंने कहाकि यह सब करके कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया।

नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती

पीएम मोदी ने कहा कि...नारी सब भूल जाती है अपना अपमान कभी नहीं भूलती। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहाकि नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से कुछ छीनने का नहीं था, नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था।

आपने ही तो मंजूरी दी थी, अब... होर्मुज में ईरान की गोलीबारी पर भारतीय जहाज ने क्या कहा था?

तेहरान (एजेंसी)। ईरान ने शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो भारतीय झंडे लगे जहाजों पर गोलीबारी की। भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया कि जिन जहाजों पर हमला हुआ, उनमें से एक की पहचान 'सैनमार हेराल्ड' के रूप में हुई है। सूत्र ने बताया कि जहाज पर सवार चालक दल और जहाज, दोनों सुरक्षित हैं। इस दौरान, ईरानी सेना और भारतीय क्रू के बीच हुई रेडियो बातचीत की ऑडियो सामने आई है। इसमें भारतीय जहाज पर मौजूद क्रू कह रहा है कि आपने ही तो मुझे गुजरने की इजाजत दी थी और अब आप ही गोली चला रहे।

ईरान द्वारा वापस लौटने पर मजबूर किए जाने से पहले जहाज ने रेडियो पर ईरानी सेना को संदेश भेजा- ''मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है! आपने मुझे आगे बढ़ने की मंजूरी दी थी। और अब आप गोलीबारी कर रहे हैं। मुझे वापस मुड़ने दीजिए।'' यह कहने के बाद भारतीय जहाज वापस लौट गया। रेडियो पर हुई यह बातचीत ठीक इसके बाद ही कट गई। गोलीबारी की घटना के बाद नई दिल्ली ने शनिवार को ईरानी राजदूत को तलब किया और होर्मुज में दो भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर विरोध दर्ज कराया। ईरान ने मध्य-पूर्व युद्ध में संघर्ष-विराम के दौरान इस रणनीतिक व्यापार मार्ग को कमर्शियल आवाजाही के लिए फिर से खोलने का अपना वादा वापस ले लिया है। यह कदम उसने इस जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा लगाई गई जवाबी नाकेबंदी के विरोध में उठाया है। यह जलमार्ग कच्चे तेल और गैस के लिए एक बेहद अहम रास्ता है। सुरक्षा पर नजर रखने वालों ने बताया कि शनिवार को जब कई कमर्शियल जहाज इस स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें ईरानी सेना की ओर से गोलीबारी और धमकियों का सामना करना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सचिव विक्रम मिस्त्री ने ईरानी राजदूत को तलब किया।

दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, तीन राज्यों से चार आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में आतंकी साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल की. खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने उन चार आरोपियों को महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से गिरफ्तार किया जो आतंकी साजिश रच रहे थे. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर 'खुरासान से काले झंडों वाली सेना' और भारतीय उपमहाद्वीप में खिलाफत स्थापित करने जैसी विचारधारा से प्रभावित थे.

स्पेशल सेल की एनडीआर टीम ने इंस्पेक्टर विनय पाल और मनोज कुमार के नेतृत्व में, एसीपी आशीष कुमार की निगरानी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस दौरान एक आरोपी के पास से आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया, जबकि सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोसाइब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम (ठाणे), मोहम्मद हम्माद (मुंबई), शेख इमरान (भुवनेश्वर) और मोहम्मद सोहेल (कटिहार) के रूप में हुई है.

बंगाल में केवल वोटर ही मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में जा सकेंगे

कोलकाता (एजेंसी)।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के दौरान स्वतंत्र व शांतिपूर्ण मतदान के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत, मतदान केंद्रों पर केवल मतदातओं को ही 100 मीटर के दायरे में जाने की इजाजत होगी। सीनियर अधिकारी ने कहा, 'मतदान केंद्रों के पास व्यवस्था बनाए रखने और अनुचित प्रवेश को रोकने के लिए 100 मीटर की परिधि तय की जाएगी। केवल मतदाताओं को ही अंदर जाने की अनुमति होगी।' उन्होंने कहा कि बूथ स्तरीय अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस सीमा के बाहर तैनात रहेंगे, जहां मतदाता दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

सीनियर अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर, अतिरिक्त जांच की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले मतदाता दस्तावेजों का दो अलग-अलग स्थानों पर दोबारा सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस उपाय का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकना है। उन्होंने कहा, 'विचार यह है कि सत्यापन के कई स्तर हों ताकि केवल वास्तविक मतदाता ही अपना वोट डाल सकें।' निर्वाचन आयोग ने मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं। मतदान कर्मियों को घर-घर जाकर पर्ची वितरित करने का निर्देश दिया गया है। पीठासीन अधिकारी उन मतदाताओं का रिकॉर्ड रखेंगे जिनसे संपर्क नहीं हो सका और इसके कारणों का भी उल्लेख करेंगे। अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन, अगर कोई मतदाता जिसे पर्ची नहीं मिली है, मतदान केंद्र पर आता है तो पीठासीन अधिकारी उसे वोट डालने की अनुमति देने से पहले मतदाता सूची में उसके नाम और फोटो का मिलान करके उसकी पहचान सत्यापित करेंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2026 में चौथी हार

सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 रनों से जीता करीबी मुकाबला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराकर तीसरी जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (59 रन) की शानदार शुरुआत के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज की धारदार गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 194 रन ही बना सकी। अभिषेक और हेनरिक क्लासेन (59 रन) के अर्धशतकों को छोड़ दें तो सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी इकाई ने सीएसके के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। जवाब में सीएसके की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 184 रन ही बना सकी और उसे चौथी हार का मुंह देखना पड़ा।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके को पहला झटका दूसरे ओवर में संजू सैमसन (07) के आउट होने से लगा जो नीतिश कुमार की गेंद पर हेनरिक क्लासेन के हाथों लपके गए। पर आयुष म्हात्रे और कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने तेजी से रन जुटाते हुए टीम को अच्छी शुरूआत कराई। इन दोनों ने 21 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी निभा ली थी। लेकिन अचानक एक रन लेते हुए म्हात्रे के पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और उपचार लेने के बावजूद उन्हें परेशानी हो रही थी। और आखिर में नीतिश कुमार ने उनकी 13 गेंद में 30 रन की पारी का अंत किया जब क्लासेन ने हवा में छलांग लगाकर उनका जबरदस्त कैप लपका।

सीएसके ने 66 रन के स्कोर पर म्हात्रे और गायकवाड़ के विकेट गंवाए। गायकवाड़ (19 रन) ईशान मलिंगा की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों लपके गए। मलिंगा ने सरफराज खान (25 रन) के रूप में अपना दूसरा विकेट लिया। डेवाल्ड ब्रेविस खाता भी नहीं खोल सके और शिवांग कुमार की गेंद पर लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट हुए। लग रहा था कि शॉर्ट (34 रन) और शिवम दुबे (21) अच्छी भागीदारी निभाकर टीम को जीत के करीब पहुंचा देंगे। पर मलिंगा की गेंद पर अनिकेत शर्मा ने डीप मिडविकेट पर शॉर्ट का शानदार कैच लपका। सीएसके ने 16वें ओवर में 148 रन पर अपना छठा विकेट खो दिया। सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

मुकेश ने दिए करारे झटके

अभिषेक (22 गेंद) ने 15 गेंद में अपना एक और अर्धशतक पूरा जिससे लग रहा था कि गायकवाड़ का फैसला उल्टा पड़ गया है। लेकिन आमतौर पर थोड़े महंगे साबित होने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी (दो ओवर में 21 रन देकर दो विकेट) ने पावरप्ले की आखिरी दो गेंदों पर ट्रेविस हेड (20 गेंद में 23 रन) और कप्तान ईशान किशन (शून्य) को आउट कर करारे झटके दिए।

इसरो 2027 में लॉन्च करेगा जी20 उपग्रह, करेगा जलवायु की निगरानी

बेंगलुरु (एजेंसी)।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 2027 में जी20 उपग्रह लॉन्च की तैयारी कर रहा है। इसको जलवायु, वायु प्रदूषण और मौसम के पैटर्न की निगरानी का अध्ययन करने का कार्य सौंपा जाएगा। इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में डीआरडीओ, इसरो और एयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष वी नारायणन ने शनिवार इसकी पुष्टि की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ भारत जी20 देशों में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण में भी बड़ी प्रगति की है। एजेंसी ने 34 देशों के 433 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जिसमें एक ही रॉकेट से 100 से अधिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना शामिल है। यह बिना किसी टक्कर के एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों के प्रक्षेपण का विश्व रिकॉर्ड है।

सरकार ने स्मार्टफोन के लिए आधार ऐप अनिवार्य करने की शर्त हटाई

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत सरकार ने स्मार्टफोन पर आधार ऐप को अनिवार्य बनाने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है। ऐपल और सैमसंग जैसी कंपनियों के विरोध के बाद सरकार ने कदम पीछे हटा लिया है। उन्होंने गोपनीयता, सुरक्षा और परिचालन संबंधी चुनौतियों को लेकर चिंता जताई थी। इस साल की शुरुआत में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्मार्टफोन निर्माताओं से नए फोन में ऐप को पहले से इंस्टॉल करने पर चर्चा करने का आग्रह किया था। रिपोर्ट के अनुसार, यूआईडीएआई) के कहा है कि आईटी मंत्रालय ने प्रस्ताव की समीक्षा की और स्मार्टफोन निर्माताओं को आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के लिए बाध्य करने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने पिछले 2 सालों में स्मार्टफोन निर्माताओं को सरकारी ऐप्स को अनिवार्य करने के लिए कम से कम 6 बार प्रयास किए। उन्होंने हर बार, यूजर की पसंद और प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए इन प्रस्तावों का विरोध किया।

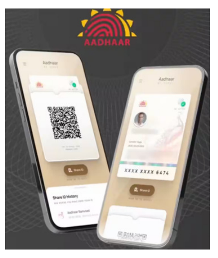

स्मार्टफोन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी निर्माता संघ ने तर्क दिया कि इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

महिला आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक

राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने शनिवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनके बयानों और कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया गया. इस दौरान हज़ारों की संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी. इस प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, सांसद कमलजीत सेहरावत, बांसुरी स्वराज, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बड़े नेता पहुंचे.

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, यहां दिल्ली की समस्त नारी शक्ति एकत्रित हुई है और इस बात का विरोध कर रही है कि कल लोकसभा में विपक्ष के लोगों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित नहीं होने दिया. सभी महिलाएं इस बात से बेहद नाराज़ हैं, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की मंशा ही इस विधेयक को पास नहीं होने देने की थी. केंद्रीय मंत्री ने इस घटनाक्रम को शर्मनाक और दुखद बताते हुए कहा कि इससे देश की महिलाओं का मनोबल टूटता है वहीं, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपना विकास विरोधी चरित्र प्रदर्शित किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल महज एक विधायी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाने का एक ऐतिहासिक कदम था. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण कभी रहा ही नहीं.

बता दें कि भारत की संसद में वर्तमान में महिलाओं के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है.

भाजपा-आरएसएस को तमिल भाषा या संस्कृति को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे: राहुल गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौरे पर पहुंचे हैं। तिरुवल्लूर जिले में स्थित पोननेरी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मंच से कहा कि भाजपा और आरएसएस को तमिल भाषा या संस्कृति को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि कल संसद में हुआ, वे (केंद्र सरकार) एक नया बिल लेकर आए। उन्होंने कहा कि वे महिलाओं से जुड़ा एक बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वे 2023 में ही महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास कर चुके थे। इसलिए, कल महिलाओं वाले बिल की आड़ में परिसीमन छिपा हुआ था। उनकी योजना संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करना थी। दक्षिणी राज्यों और छोटे राज्यों की ताकत को कमजोर करना और पूर्वोत्तर राज्यों की ताकत को कमजोर करना था। कल हमने संसद भवन में उस बिल को हरा दिया।

राहुल गांधी ने कहा, हमने भारत के उस विचार की रक्षा के लिए इस बिल का विरोध किया और इसे हराया, जो हमारे संविधान में निहित है। भारत, यानी भारतवर्ष, राज्यों का एक संघ है, जहां हर राज्य की अपनी एक आवाज होनी चाहिए।

प्रियंका गांधी बोली- सरकार की मंशा महिला आरक्षण की नहीं, केवल और केवल परिसीमन की थी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत सरकार ने स्मार्टफोन पर आधार ऐप को अनिवार्य बनाने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है। ऐपल और सैमसंग लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा विधेयक गिर जाने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इन विधेयकों को सरकार की साजिश बताया। उन्होंने कहा, पूरी साजिश इसलिए रची गई, ताकि भाजपा सत्ता में रह सके। अभी नहीं किया गया तो ये जो परिसीमन करना चाह रहे हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर वो नहीं हो पाएगा। महिला आरक्षण के नाम पर ये परिसीमन करना चाह रहे थे।

प्रियंका ने कहा, 2011 की जनगणना के आधार पर होता, तो उन्हें जाति आरक्षण भी नहीं लेना होता। उन्होंने सोचा कि पारित हो गया तो हम महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। महिलाओं के संदर्भ में हमारा एक इतिहास है। महिलाओं ने उन्नाव, हाथरस, मणिपुर और ओलिंपिक की महिलाओं को देखा है। ये स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण की नहीं, केवल परिसीमन की बात थी। इनको मनमानी की पूरी आजादी मिल जाती।

प्रियंका ने कहा, महिलाएं बेवकूफ नहीं है, सब देख रही हैं। अगर आप वाकई महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो जो 2023 में विधेयक पारित हुआ था, वो लाइए। इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। आप इसे घूमा फिराकर मत करिए। कल जो हुआ वो लोकतंत्र की जीत हुई है, विपक्ष की जीत हुई है।

कक्षा एक से 10वीं तक मराठी नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा एक से 10वीं तक मराठी भाषा अनिवार्य की गई है. लेकिन जो स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला सरकार ने किया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक विस्तृत प्रक्रिया तय की है और इस संबंध में एक सरकारी निर्णय (जीआर) जारी किया है।

सरकारी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से ही राज्य भर के स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी एक अनिवार्य विषय है। यह नियम महाराष्ट्र अनिवार्य शिक्षण और मराठी भाषा अधिगम अधिनियम, 2020 के लागू होने के साथ अनिवार्य किया गया था। अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे पहला नोटिस दिया जाएगा और 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगले शैक्षणिक वर्ष से मराठी विषय को अनिवार्य रूप से शुरू करने के आदेश भी जारी किए जाएंगे।

बिहार के सभी 38 जिलों में बनेंगे एयरपोर्ट? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों से मांगा प्लान

पटना (संवाददाता)।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहरों के विस्तारीकरण की दीर्घकालीन योजना पर काम तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल विमानन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से काम करना होगा। साफ-सफाई, यातायात, शहरों के विस्तार को लेकर जो अर्बन नक्शा बनाएं. उसको डिजिटलाइज कर लोगों को जानकारी में दें। साथ ही सभी जिलों में हवाई अड्डों के विकास को लेकर एक प्लान तैयार करें।

सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल विमानन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने शहरों के विस्तारीकरण की दीर्घकालीन योजना पर काम तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों में साफ-सफाई, यातायात सुविधा और नगरीय क्षेत्र के विस्तार को लेकर जो नक्शा बनता है, उसे डिजिटलाइज कर सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एरोसिटी के विकास की दिशा में भी ठोस पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास कमर्शियल कॉम्पलेक्स, होटल, लॉजिस्टिक पार्क और पर्यटन आधारित संरचनाएं विकसित करने की योजना है। साथ ही, राज्य के छोटे एवं क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्कता प्राप्त होगी।

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान करें और इसके संबंध में पर्यटकों तक सहज और सरल ढंग से जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था सुदृढ़ करें। बिहार में बहुत कार्य किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ब्रांडिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का प्रयोग रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अच्छे ढंग से करें। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, गृह विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

तीनों विभाग के प्रधान सचिव ने सीएम को दिया अपडेट

समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने 11 सैटेलाइट, ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास के रोडमैप की जानकारी दी। सिविल विमानन विभाग के सचिव निलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि पटना एवं गयाजी से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं सकारात्मक बदलाव के संबंध में प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा लोगों को बेहतर ढंग से जागरुक किया जा रहा है।

BPSC AEDO परीक्षा में कदाचार और पेपर लीक की जांच करेगी ईओयू, एसआईटी गठित

नालंदा (संवाददाता)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) प्रतियोगी परीक्षा में कदाचार और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) करेगी। ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मुंगेर और नालंदा जिले से जुड़े दो मामलों में ईओयू ने केस दर्ज किया है। ईओयू के एसपी प्रशासन राजेश कुमार के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है।

एसआईटी में एक डीएसपी और पांच इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। गठित एसआईटी के सहयोग के लिए एसटीएफ के डीएसपी विनय कृष्ण और साइबर सुरक्षा इकाई से दो पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध भी पुलिस मुख्यालय से किया गया है।

ईओयू के एडीजी ने एसआईटी के सभी सदस्यों को साक्ष्य संकलन करते हुए मामले की सही तरीके से जांच के निर्देश दिए हैं। गठित एसआईटी की समीक्षा ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लन करेंगे और एडीजी को जांच के बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग ने एईडीओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से इनकार किया है। आयोग का कहना है कि मुंगेर में पिछले दिनों एईडीओ परीक्षा से एक दिन पहले गड़बड़ी की साजिश रचने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 20 अभ्यर्थी और एक केंद्राधीक्षक शामिल हैं। हालांकि, 14 अप्रैल को हुई पहले दिन की परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। वहीं, नालंदा जिले में एईडीओ परीक्षा में कदाचार के मामले में एक महिला अभ्यर्थी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को सोहरसराय के एक परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक ने महिला अभ्यर्थी को नकल करते हुए पकड़ा था। इसके बाद उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया था।

935 पदों पर होनी है भर्ती

बीपीएससी ने पिछले साल सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर भर्ती निकाली थी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बाद इस महीने परीक्षा आयोजित की गई। 14 अप्रैल को एईडीओ भर्ती परीक्षा का पहला दिन था। इसके बाद 15, 17 और 18 अप्रैल को भी इसका आयोजन किया गया। अब सोमवार को एईडीओ एग्जाम होगा। आखिरी दिन की परीक्षा 21 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों से भाषा और जनरल एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। एईडीओ का रिजल्ट जून महीने में आने की संभावना है। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

मोतिहारी में जहरीली शराब से एक और जान गई! बावर्ची की मौत के बाद युवक पुलिस हिरासत में

मोतिहारी (संवाददाता)। बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराबकांड में बीते दिनों 10 लोगों की जान जाने के बाद अब एक और युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। ताजा घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के टिकैता गोविंदपुर पंचायत की है। बावर्ची का काम करने वाले एक शख्स की शुक्रवार रात को जान चली गई। परिजन का कहना है कि उसने शराब पी थी। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है।

मृतक की पहचान 40 वर्षीय बनारसी साह के रूप में हुई है। वह मूलरूप से रघुनाथपुर के रहने वाले थे। करीब 20 सालों से वह अपने ससुराल गोविंदापुर में ही परिवार के साथ रह रहे थे। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की रात करीब 9 बजे गांव के ही एक भोला नामक व्यक्ति ने बनारसी साह को शराब लाकर दी थी। पत्नी फूलकुमारी देवी ने उन्हें शराब पीने से मना भी किया। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी।

परिजन की मानें तो शराब पीने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होते देख परिजन उन्हें आनन-फानन में ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के साला गोपी साह ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब पीने से उनके बहनोई की मौत हुई है। बनारसी साह बावर्ची का काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि विसरा जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और हर पहलू से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही शनिवार की सुबह तुरकौलिया थानाध्यक्ष सम्पत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने भोला नाम के युवक को हिरासत में लिया है। हालांकि वह शराब देने की बात से इनकार कर रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाद में उसे परिजनों को सौंप दिया।

वहीं, पूरे पंचायत क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। लेकिन कहीं से भी शराब बरामद नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गत दो सप्ताह के भीतर मोतिहारी के रघुनाथपुर और तुरकौलिया क्षेत्र के बालगंगा, परसौना, शंकरसरैया, हरदिया समेत कई गांवों में जहरीली शराब पीने से करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि एक दर्जन से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी।

5 करोड़ की जमीन के लिए बेटा बन गया कपूत, ससुर के साथ मिलकर पिता पर चलवाई गोली

पटना (संवाददाता)। बिहार की राजधानी पटना से बाप-बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र निवासी खटाल संचालक शिव कुमार यादव की हत्या की साजिश उसके बेटे ने ही रची थी। लगभग 5 करोड़ रुपये की जमीन के लिए बेटे ने अपने ससुर के साथ मिलकर पिता पर गोली चलवाई। हालांकि, इस घटना में पिता की जान बच गई थी।

इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने खटाल संचालक के बेटे दीपक कुमार, समधी मिथिलेश यादव और मिथिलेश के रिश्तेदार नरेश यादव तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर दो कट्टा, तीन कारतूस, वारदात में प्रयुक्त बाइक, एक खोखा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना मध्य सिटी एसपी दीक्षा ने शनिवार को बताया कि पिछले महीने 14 मार्च की रात खटाल संचालक शिव कुमार यादव एजी कॉलोनी स्थित अपने खटाल में सो रहे थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग कर हमला किया गया था। जख्मी हालत में उन्हें पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। समय पर सही इलाज मिलने से उनकी जान बच गई थी। इस संबंध में शिव कुमार यादव के बयान पर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीड़ित ने इस घटना में अपने बेटे के शामिल होने का शक जताया।

शादी से पहले दुल्हन के अश्लील फोटो वायरल

फेसबुक और इंस्टा पर बना फर्जी अकाउंट; केस दर्ज

मुजफ्फरपुर (संवाददाता)। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी से चंद दिन पहले ही दुल्हन के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इससे शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। बारात आने से 5 दिन पहले दुल्हन थाने पहुंच गई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए केस दर्ज कराया। दुल्हन का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से उसके नाम का एक फेक अकाउंट बनाकर उसके अश्लील फोटो पोस्ट किए गए हैं।

यह मामला मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवती ने एफआईआर दर्ज कराते हुए अमर कुमार नाम के एक व्यक्ति और उसके सहयोगियों पर डिजिटल और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी सगाई हो चुकी है और 20 अप्रैल को उसकी शादी होने वाली है।

युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसके नाम से फर्जी आईडी बना ली। फिर उसके जरिए युवती की अश्लील फोटो उसके रिश्तेदार और परिचितों को आरोपी भजे रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसकी शादी तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और उसे सार्वजनिक रूप से जलील कर रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह नौकरी करती थी, तब कार्यस्थ से अमर कुमार और उसके सहयोगियों ने उसका अपहरण किया था। वे उसे एक होटल के कमरे में लेकर गए थे। वहां उसकी बेल्ट और लात-घूंसों से पिटाई की गई। फिर आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने मोबाइल फोन पर उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं।

जब पीड़िता की सगाई हुई तो शादी से कुछ दिन पहले ही आरोपी उसे प्रताड़ित करने के लिए अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी उन तस्वीरों के जरिए उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। शादी तय होने पर उससे 7 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की जा रही है। पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी से ठीक पहले दुल्हन के अश्लील फोटो वायरल होने और उसे प्रताड़ित किए जाने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

डबल मर्डर से थर्राया शेखपुरा

थ्रेसर हटाने के लिए चचेरे भाइयों में अंधाधुंध फायरिंग; दो लोगों की मौत

शेखपुरा (संवाददाता)।

बिहार का शेखपुरा जिला डबल मर्डर से थर्रा उठा। सिरारी थाना क्षेत्र के अकौना गांव में थ्रेसर हटाने के मामूली विवाद में चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें एक बुजुर्ग समेत दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल बन गया। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

जानकारी के अनुसार, अकौना गांव निवासी राजेश कुमार और प्रेम राज उर्फ संतोष कुमार के बीच थ्रेसर हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच मारपीट होने लग गई। देखते ही देखते उनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई।

इसी दौरान झगड़ा शांत कराने पहुंचे 65 वर्षीय पूना यादव को सिर में गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार रात को हुई इस घटना के बाद माहौल और बिगड़ गया। आरोप है कि संतोष कुमार ने रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। इसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में संतोष कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन-फानन में सदर अस्पताल शेखपुरा ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। स्थिति को देखते हुए इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी के निर्देश पर एएसपी डॉ. राकेश कुमार के नेतृत्व में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें दोनों पक्षों से कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ऐक्शन में पुलिस

एसपी बलिराम कुमार ने बताया कि थ्रेसर हटाने के विवाद में दो चचेरे भाइयों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग सहित दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच में जुटी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस खौफनाक वारदात में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

पूर्णिया में अर्धनग्न हालत में मिली पति की लाश, पहली बीवी बोली- दूसरी वाली ने मार दिया

भवानीपुर (संवाददाता)। बिहार के पूर्णिया जिले में शनिवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के गोंदवारा पतकेली पंचायत स्थित तुर्की मुसहरी टोला की है। मृतक की पहचान शेखपुरा सब्जी टोला वार्ड नंबर 6 निवासी मोहम्मद सोहराब के रूप में हुई है। उसकी उम्र 45 साल थी। मृतक की पहली पत्नी ने आरोप लगाया है कि दूसरी बीवी ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर ही है।

सोहराब का शव खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर भवानीपुर थानाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, एसआई शैलेश सिंह, विकास कुमार, अमित कुमार पीएसआई श्रुति कुमारी, शिवेश कुमार मिश्रा सदल बल घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह मक्का खेत गए किसानों ने देखा कि अर्धनग्न अवस्था में एक शख्स का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया। मक्का के खेत में शव की बात समूचे क्षेत्र में फैलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। बाद में शव की पहचान सोहराब के रूप में की गई।

घटना की जानकारी मिलते ही सोहराब की पहली पत्नी और परिजन भी वहां पहुंचे। पहली पत्नी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को बताया कि सोहराब लगभग 12 साल से तुर्की मुसहरी में कथित दूसरी पत्नी भीखमा देवी के साथ रहते थे। परिजनों ने बताया कि वह कभी-कभार ही अपने घर शेखपुरा सब्जी टोला आता था। सोहराब की पहली पत्नी ने उसके दूसरी पत्नी पर सोहराब की साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, मृतक की कथित दूसरी पत्नी भीखमा देवी ने बताया कि सोहराब शुक्रवार की शाम को खेत देखने की बात कहकर निकले थे, मगर वापस नहीं लौटे और शनिवार को उनका शव खेत में मिला।

ग्रामीण विकास को नई रफ्तार : 2426 किमी सड़क निर्माण का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास

रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर स्थित रणजीता स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-04) के अंतर्गत स्वीकृत 774 सड़कों का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। इन सड़कों की कुल लंबाई 2426.875 किलोमीटर है, जिनके निर्माण पर 2225.44 करोड़ की लागत आएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिला मुख्यालय स्थित वशिष्ठ कम्यूनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सड़कों का भूमिपूजन ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के निर्माण से लगभग 781 बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़क सुविधा प्राप्त होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, जो उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है और आज यह योजना ग्रामीण भारत की जीवनरेखा बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में सड़क नेटवर्क के विस्तार में अभूतपूर्व तेजी आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के माध्यम से राज्य के अधिकांश गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तथा रायपुर से जशपुर होते हुए धनबाद तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे जशपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सहकारिता क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि हाल ही में 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, जिससे प्रदेश में समितियों की संख्या बढ़कर 2573 हो गई है। ये समितियां किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके निकट उपलब्ध कराएंगी तथा धान विक्रय प्रक्रिया को सरल बनाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और होली से पूर्व 25.28 लाख किसानों के खातों में 10000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरण कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नागरिकों से आगामी जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि सही आंकड़े ही सटीक विकास योजनाओं का आधार बनते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत प्रदेशभर में शिविर आयोजित कर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है तथा 757 करोड़ के बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे अब दूरस्थ क्षेत्रों में भी तेजी से विकास कार्य संभव हो पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि आज जिन 774 सड़कों का शिलान्यास किया गया है, उनका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में 1300 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे ये क्षेत्र भी मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में धर्म स्वातंर्त्य कानून लागू कर अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारीक ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-04 के अंतर्गत राज्य में 3065 सड़क विहीन बसाहटों का चिन्हांकन किया गया है। बैच-2 में 1000 बसाहटों के लिए 2684 किलोमीटर लंबाई की 975 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जबकि शेष 1284 बसाहटों के लिए डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के लिए 2902 किलोमीटर लंबाई की 807 सड़कों एवं 123 वृहद पुलों के निर्माण हेतु 2477 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनसे 871 बसाहटें लाभान्वित होंगी। अब तक 1735 किलोमीटर लंबाई की 356 सड़कें पूर्ण कर 356 बसाहटों को जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक कुल 47,847 किलोमीटर लंबाई की 10,119 सड़कों एवं 581 वृहद पुलों को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 42,250 किलोमीटर लंबाई की 8713 सड़कें और 444 पुल पूर्ण किए जा चुके हैं। जशपुर जिले में इस योजना के तहत कुल 77 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लंबाई 197.26 किलोमीटर तथा लागत ?196.20 करोड़ है। विभिन्न विकासखंडों में इन सड़कों का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, जिससे जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुदृढ़ होगी और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

सबई घास से रस्सी निर्माण कर आत्मनिर्भरता की राह, वनधन विकास केंद्र केड़ना की प्रेरक पहल

रायपुर।

ग्रामीण अंचलों में आजीविका के सीमित साधनों के बीच जब स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है, तब सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है धर्मजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत वनधन विकास केंद्र केड़ना की, जहाँ सबई घास से रस्सी निर्माण ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाया है।

वन विभाग की अधिकारियों ने आज यहाँ बताया कि सबई घास रायगढ़ जिले के वन क्षेत्रोंकृजमझोर, केड़ना, सोलमुड़ा, सोरझुड़ा, अन्नोला एवं पेलमाकृमें प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाएं इससे हाथ से रस्सी बनाकर घरेलू उपयोग या स्थानीय बाजारों में सीमित स्तर पर बिक्री करती थीं। हालांकि, बाजार तक सीधी पहुंच और उचित मूल्य न मिलने के कारण यह कार्य बड़े पैमाने पर आय का साधन नहीं बन पा रहा था। इसी कड़ी में राज्य सरकार की वनधन योजना के अंतर्गत वनधन विकास केंद्र केड़ना की स्थापना कर महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया गया। उन्हें सबई घास से रस्सी निर्माण के लिए हाथों एवं विद्युत चालित मशीनें उपलब्ध कराई गईं। स्तर ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। इससे महिलाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ी और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ।

दरअसल सबई घास से निर्मित रस्सी का उपयोग बांस के बंडलों को बांधने में किया जाता है, जिसकी मांग वन विभाग एवं पेपर उद्योग में लगातार बनी रहती है। वन विभाग द्वारा सबई रस्सी को 45 रुपये प्रति किलो की दर से क्रय किया जाता है, जिससे महिलाओं को मजदूरी के रूप में नियमित आय प्राप्त हो रही है। वहीं तैयार रस्सी को विभिन्न वनमंडलों में 75 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय कर वनधन केंद्र को भी लाभ मिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्षों में वनधन केंद्र केड़ना से जुड़ी महिलाओं ने 30 से 40 क्विंटल रस्सी का निर्माण कर 1.5 से 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित की। वर्ष 2025-26 में 150 क्विंटल रस्सी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 7 से 8 लाख रुपये की आय ग्रामीण महिलाओं को होने की संभावना है। मार्च 2026 तक कुल 11.25 लाख रुपये मूल्य की रस्सी निर्माण कर 7.50 लाख रुपये मजदूरी के रूप में ग्रामीणों को प्राप्त होने का अनुमान है। यह परियोजना पूरी तरह ईको-फ्रेंडली है। सबई घास का विनाश रहित दोहन किया जाता है, जिससे वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। भविष्य में भू-क्षरण प्रभावित क्षेत्रों में सबई घास रोपण की योजना भी प्रस्तावित है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। वनधन विकास केंद्र केड़ना की यह पहल इस बात का सशक्त उदाहरण है कि यदि स्थानीय संसाधनों का वैज्ञानिक और संगठित उपयोग किया जाए, तो ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सबई घास से रस्सी निर्माण ने न केवल रोजगार सृजन किया है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की नई उम्मीद भी जगाई है।

मुख्यमंत्री ने किया 'वूमेन फॉर वेटलैण्ड्स' अभियान के तहत पोस्टर का विमोचन

रायपुर।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में 'वुमेन फॉर वेटलैण्ड्स' अभियान के पोस्टर का अनावरण किया,इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आर्द्रभूमि एवं प्राकृतिक जल-स्त्रोतों के संरक्षण हेतु चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल ही जीवन है और आर्द्रभूमियां मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति को इस पवित्र अभियान से जोड़ना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायी कदम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि 'नदियां, तालाब, कुएं, पोखर और आर्द्रभूमियां केवल जल-स्त्रोत नहीं, बल्कि जीवनदायिनी प्रकृति की पहचान हैं। इन्हें बचाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। 'वूमेन फॉर वैटलैंड्स' अभियान की संस्थापक एवं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी द्वारा प्रदेशभर में आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के अंतर्गत तालाब, नहर, कुएं, नदियों एवं प्राकृतिक जल-स्त्रोतों के संरक्षण के लिए महिलाओं को संगठित किया जा रहा है। प्रज्ञा निर्वाणी ने मुख्यमंत्री को नवागढ़ स्थित गिधवा-परसदा-नगधा पक्षी विहार क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने हेतु ज्ञापन भी सौंपा, मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'महिलाएं प्रकृति की प्रथम संरक्षक हैं,यदि मातृशक्ति आगे आएगी तो जल-स्त्रोतों का संरक्षण जन-आंदोलन बन जाएगा।' पोस्टर अनावरण कार्यक्रम के दौरान प्रसन्ना अवस्थी, प्राची शर्मा, प्रणीता शर्मा, आरविका अवस्थी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

अम्बिकापुर में विकास को नई रफ्तार

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने 7 करोड़ की लागत से बनने वाले 120 मीटर लंबे पुल का किया भूमि पूजन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अम्बिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव-पनगोती मार्ग पर स्थित भालू नाला पर पुल निर्माण एवं पहुँच मार्ग के कार्य का आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस पुल की लंबाई 120 मीटर तथा पहुँच मार्ग की लंबाई 362 मीटर होगी। इस पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा और विशेष रूप से बड़गांव, पनगोती सहित आसपास के कई गांवों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक बारिश के मौसम में बाधित रहने वाला यह मार्ग पुल बनने के बाद वर्षभर सुगम और सुरक्षित रहेगा, जिससे स्थानीय जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मंत्री श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क और पुल जैसी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के अवसर भी बढ़ते हैं। अम्बिकापुर के समग्र विकास और क्षेत्रवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ की गई यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस जन-उपयोगी कार्य के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है और उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री साय ने 'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया' महाअभियान अंतर्गत 500 नए तरिया का किया शिलान्यास

आजीविका डबरी और नए तरिया से किसानों व ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा लाभ

रायपुर।

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल 'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया महाअभियान' का आज जशपुर के रणजीता स्टेडियम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत 'नवा तरिया, आय के जरिया' के तहत प्रदेश में 500 नए तरिया (तालाब) के निर्माण का भी शिलान्यास किया। इससे जल संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और कृषि कार्यों के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर कार्य किए जाएंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत इस महाअभियान के तहत प्रदेशभर में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 15 अप्रैल 2026 तक 13,000 से अधिक डबरी निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। यह उपलब्धि अभियान की गति और प्रभावशीलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि जल ही जीवन और विकास का आधार है। 'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया' अभियान के माध्यम से हम गांव-गांव में जल संरक्षण को जन आंदोलन बना रहे हैं। इससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आजीविका डबरी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन, बत्तख पालन, सिंघाड़ा उत्पादन, सब्जी उत्पादन और वृक्षारोपण जैसे विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण स्तर पर इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए दीवार लेखन, बैनर, ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान तथा क्यूआर कोड के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी व्यापक प्रचार किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आजीविका डबरी से जुड़े कार्यों में स्व सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हितग्राही परिवार की महिला सदस्य का नाम नागरिक सूचना पटल में अंकित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की अधिकारिता और भागीदारी मजबूत हो सके। इसके तहत उन्नत तकनीक आधारित योजना निर्माण और ग्राम सभा की स्वीकृति के आधार पर कार्यों को मंजूरी दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो रही है। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से यह अभियान ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य करेगा। 'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया' महाअभियान जशपुर सहित पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाते हुए ग्रामीणों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभर रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, अध्यक्ष छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल श्री रामप्रताप सिंह, विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

किसानों के हित सर्वोपरि

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अमानक बीज मामले में कार्रवाई, नुन्हेम्स कंपनी पर एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने करेला की फसल में अमानक बीज और रोपे से हुए भारी नुकसान का मामला रखा, जिस पर श्री शिवराज सिंह ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार मानते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देशों के बाद मामले में तेज़ कार्रवाई हुई और धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी- नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने नई दिल्ली में उनसे भेंट कर करेला फसल में अमानक बीज और रोपे के कारण हुए गंभीर नुकसान की जानकारी दी, जिस पर श्री चौहान ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को साफ कहा कि प्रभावित किसानों को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस कंपनी की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हुई और मनावर थाना, जिला धार में एफआईआर क्रमांक 266 दर्ज की गई। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 318(4) और 324(5), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराएं 3 व 7 तथा बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्राथमिकी में नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है।

किसानों की शिकायत है कि उन्होंने नवंबर 2025 में विभिन्न नर्सरियों और कृषि सेवा केंद्रों से संबंधित इस कंपनी के बीज और रोपे खरीदे थे, लेकिन बुआई और रोपण के बाद करेला फसल में अपेक्षित उत्पादन नहीं हुआ और फल छोटे, पीले होकर गिरने लगे। फसल उत्पादन में आई भारी गिरावट के बाद किसानों ने 17 फरवरी 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अमानक बीज एवं अमानक बीज से तैयार रोपे किसानों को प्रमाणित बताकर बेचे गए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा। किसानों ने जब दिल्ली आकर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह को ये सब बातें बताई तो श्री चौहान ने कहा कि यह मामला केवल फसल खराब होने का नहीं, बल्कि किसानों के भरोसे, मेहनत और पूंजी को नुकसान पहुंचाने का है। श्री शिवराज सिंह के निर्देश पर इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वैधानिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच आगे बढ़ाई गई है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की बात सुनते ही यह सख्त संदेश दिया कि किसान के साथ अन्याय, लापरवाही या धोखाधड़ी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी और सरकार पीड़ित किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। धार और खरगोन के किसानों से जुड़ा यह घटनाक्रम बताता है कि जब किसानों की समस्या सीधे केंद्रीय मंत्री श्री चौहान तक पहुंची, तो उस पर केवल औपचारिक संज्ञान नहीं लिया गया, बल्कि मुआवजा और सख्त कार्रवाई दोनों मोर्चों पर ठोस पहल की गई है। इससे किसानों में यह भरोसा मजबूत हुआ है कि उनकी आवाज़ सुनी भी जा रही है और उस पर परिणामकारी कार्रवाई भी हो रही है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में इससे पहले भी शिकायतों के त्वरित निवारण, अमानक एवं नकली बीज-कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा किसानों को वास्तविक राहत दिलाने के पक्ष में लगातार स्पष्ट और कठोर निर्देश दिए हैं। घटिया बीज और कृषि आदानों के मामले में श्री चौहान बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों की मेहनत, फसल और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित जननायक स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 99वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

50 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, दुनिया की सबसे गर्म जगहों की लिस्ट में भारत के कई शहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में इस बार गर्मी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और सामान्य से अधिक गर्मी का असर साफ नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस सप्ताह महाराष्ट्र के कई जिलों में लू (हीटवेव) का अलर्ट जारी किया है। विदर्भ क्षेत्र का अकोला लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया है। इसके अलावा अमरावती, वर्धा और नागपुर भी शीर्ष गर्म शहरों की सूची में हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हीटवेव और अधिक तीव्र हो सकती है।

आईएमडी के अनुसार, 2026 में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। मार्च से मई के बीच हीटवेव की घटनाएं बढ़ सकती हैं और तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। चरम स्थिति में कुछ क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई गई है।

वैश्विक तापमान की बात करें तो चीन के युन्नान प्रांत का जिंगहोंग 37 डिग्री सेल्सियस के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा, जबकि ओडिशा के बलांगीर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भारत और आसपास के कई शहरों में भी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया गया।

बीजेपी विधायक के बेटे ने 5 लोगों को थार से कुचला, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

शिवपुरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 5 लोगों को थार से उड़ाने वाले विधायक पुत्र की दबंगई से लोग हैरान हैं. विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे ने पैदल चल रहे राहगीरों को अपनी थार गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे 5 राहगीर घायल हो गए हैं. हद तो तब हो गई जब विधायक के बेटे ने अपनी सफाई में दबंगई दिखाते हुए ये कह दिया कि जब सायरन बजाया तो राहगीर सड़क से क्यों नहीं हटे? दिनेश लोधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

शिवपुरी के करैरा में गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे दिनेश लोधी ने अपनी थार से 5 लोगों को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार तीन मजदूर और पैदल चल रहीं दो महिलाएं घायल हो गईं. मामला करैरा थाना क्षेत्र का है. दिनेश लोधी बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे हैं. मामले में फरियादी संजय परिहार निवासी ग्राम संहेड़ा, ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया, हम अपने साथियों आशीष परिहार और अंशुल परिहार के साथ बाइक से थनरा गांव मजदूरी के लिए जा रहे थे. आगे दो महिलाएं पैदल चल रही थीं. तभी थार ने हमें टक्कर मार दी.

घायल आशीष परिहार और अंशुल परिहार ने बताया, थार वाहन को विधायक के बेटे दिनेश लोधी चला रहे थे. गाड़ी के आगे प्रीतम लोधी और पीछे विधायक लिखा हुआ था, जिससे वाहन की पहचान स्पष्ट हो रही थी. वहीं, घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें आरोपी दिनेश लोधी घायलों से बहस करते नजर आ रहा है. वीडियो में वह यह कहते हुए दिखता है कि हॉर्न बजाया था फिर भी लोग रास्ते से क्यों नहीं हटे. वह सुबह जिम जाने के लिए निकला था.

इस मामले में करैरा थाना प्रभारी विनोद छावई ने कहा, दिनेश लोधी के खिलाफ अपराध क्रमांक 255/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125 (ए) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी यह भी आ रही है कि खुद विधायक पुत्र ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है. साथ ही यह भी कहा है कि कानून तोड़ने वाला कोई भी हो, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो कानून की कार्रवाई जरूरी है.

रोमांस होता तो अब तक बच्चे हो गए होते

चिराग पासवान संग अफेयर की खबरों पर बोली कंगना रनौत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बॉलीवुड की 'क्वीन' और भारतीय जनता पार्टी की तेजतर्रार सांसद कंगना रनौत हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ अपने रिश्तों को लेकर चल रही तमाम अटकलों और अफवाहों पर खुलकर विराम लगा दिया है।

कंगना ने चिराग के साथ अफेयर की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए ऐसा मजेदार जवाब दिया, जिसकी हर तरफ भारी चर्चा हो रही है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा तंज कसा।

संसद भवन के बाहर और अंदर चिराग पासवान के साथ अपनी बॉन्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज पर बात करते हुए कंगना ने साफ किया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्ट्रेस ने कहा कि वह चिराग को पिछले दस सालों से जानती हैं और वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अफेयर की खबरों को नकारते हुए कंगना ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उनके बीच कोई रोमांस होता, तो अब तक उनके बच्चे भी हो गए होते। कंगना के इस बेबाक जवाब ने सोशल मीडिया पर चल रही सभी गॉसिप्स की हवा निकाल दी है। इस इंटरव्यू के दौरान जब राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया, तो कंगना ने अपने चिर-परिचित अंदाज में चुटकी ली।

उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि वह राहुल गांधी के सिर पर बेवजह ऐसा कोई 'ताज' नहीं पहना सकतीं, जिसके वह असल में हकदार ही नहीं हैं। वहीं, दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा कि पीएम मोदी का व्यक्तित्व और उनकी नीतियां पूरी तरह समानता पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कोई भी नेता महिला वोटरों को खुश क्यों नहीं करना चाहेगा।

संसद में अब रास्ता बदल लेते हैं चिराग

कंगना रनौत और चिराग पासवान ने साल 2011 में आई बॉलीवुड फिल्म 'मिले ना मिले हम' में एक साथ स्क्रीन शेयर की थी। यह फिल्म चिराग की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई थी, जिसके फ्लॉप होने के बाद उन्होंने राजनीति का रुख कर लिया था। 2024 के लोकसभा चुनावों में दोनों नेताओं की शानदार जीत के बाद जब वे संसद में मिले, तो उनकी हंसी-मजाक की तस्वीरें जमकर वायरल हुई थीं। इससे पहले अपनी फिल्म 'इमरजेंसी' के प्रमोशन के दौरान भी कंगना ने हंसते हुए मीडिया से कहा था, प्लीज कम से कम संसद में तो हमें बख्श दीजिए। कंगना ने चुटकी लेते हुए बताया था कि लोग सिर्फ इसलिए उनके पीछे पड़े हैं क्योंकि चिराग ने उन्हें कुछ बार हंसा दिया था और अब हालत यह है कि अफवाहों के डर से चिराग उन्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं।

तमिलनाडु चुनाव 2026 के बीच जब्ती 800 करोड़ के पार, 2021 के मुकाबले लगभग दोगुनी

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में चल रहे चुनावी माहौल के अब तक करीब 800 करोड़ रुपए की नकदी, कीमती सामान और अवैध वस्तुएं जब्त की जा चुकी हैं। यह आंकड़ा 2021 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले लगभग दोगुना है। चुनाव विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 2021 के चुनाव में 446.28 करोड़ रुपए के उपहार और कीमती धातुएं बिना वैध दस्तावेज के जब्त की गई थीं। इसके अलावा 236.70 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी पकड़ी गई थी।

खास बात यह रही कि जब्त किए गए सामान में से 50 प्रतिशत से ज्यादा बाद में सही दस्तावेज दिखाने पर लोगों को वापस लौटा दिए गए थे। उस समय कुल जब्ती में केवल सोने की हिस्सेदारी ही 173.19 करोड़ रुपए की थी। वहीं, इस बार स्थिति और ज्यादा सख्त नजर आ रही है। बुधवार तक करीब 800 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है, जिसमें नकदी, आभूषण, नशीले पदार्थ और शराब शामिल हैं। अब तक 126.64 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी जब्त की गई है, जिसके पास वैध कागजात नहीं थे।

चतरा-हजारीबाग बॉर्डर पर हुआ नक्सलियों का एनकाउंटर

15 लाख का इनामी शहदेव महतो सहित चार नक्सली ढेर

रांची (एजेंसी)। झारखंड के चतरा में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. चतरा और हजारीबाग बॉर्डर पर हुए भीषण मुठभेड़ में चार कुख्यात नक्सली मारे गए हैं. मारे गए चार नक्सलियों में 15 लाख का इनामी नक्सली शहदेव महतो और नताशा भी शामिल हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय सूत्रों ने चार नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है. मुठभेड़ स्थल से दो एके 47 राइफल सहित कई हथियार बरामद किए गए हैं.

हजारीबाग पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चतरा पुलिस और कोबरा कमांडो की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए चार नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए नक्सलियों में 15 लाख रुपये के इनामी शहदेव महतो, महिला नक्सली नताशा और बुद्धदेव शामिल हैं. चौथे नक्सली की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार, शहदेव महतो अपने साथियों के साथ हजारीबाग के केराडरी जंगल क्षेत्र से गुजर रहा था. हजारीबाग पुलिस को उनके मूवमेंट की सूचना मिलते ही चतरा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू कर दिया गया. अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए कोबरा कमांडो टीम को भी शामिल किया गया. नक्सली हजारीबाग की सीमा पार कर चतरा जिले के जंगल में पहुंच गए.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। परिसीमन और महिला आरक्षण पर लोकसभा में जारी बहस के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए जादूगर का जिक्र किया। दरअसल, राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान एक जादूगर की कहानी सुनानी शुरू की, जिसे लेकर सदन में शोर-शराबा बढ़ गया।

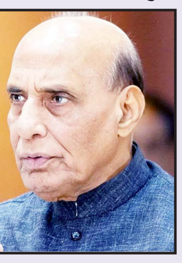

इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें टोका और कहा कि सदन की कार्यवाही मर्यादा में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और संसद की गरिमा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। ओम बिरला ने कहा, यह संसद है, चौराहा नहीं। जो बातें बाहर कही जाती हैं, वे यहां नहीं कही जा सकतीं। संसद की अपनी मर्यादा और गरिमा होती है। उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे विधेयक के मुद्दे पर ही केंद्रित रहें।

राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गैर-संवैधानिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस व्यक्ति को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान है। राजनाथ सिंह ने मांग की कि राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए और उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूचबिहार ज़िले के दिनहाटा में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया।

मनी लॉन्ड्रिंग में मर्लिन ग्रुप सहित कईयों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी

कोलकाता (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता में मर्लिन ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के अंतर्गत कई जगहों पर तलाशी अभियान चला रहा है। यह कार्रवाई मर्लिन ग्रुप के प्रोजेक्ट में कथित जालसाजी और गलत दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़ी है। ईडी की टीम ने कोलकाता और आसपास के इलाकों में सात स्थानों पर छापेमारी की। इनमें मर्लिन ग्रुप से जुड़े व्यक्ति और कंपनियों के ठिकाने शामिल हैं। जांच का मुख्य फोकस कोलकाता के आनंदपुर इलाके में चल रहे करीब 600 करोड़ रुपए के मर्लिन नियासा प्रोजेक्ट पर है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में जमीन की मालिकाना हक की जाली श्रृंखला बनाई गई और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। इससे सार्वजनिक निवेश को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है।

तलाशी के दौरान ईडी की टीम ने सुशील कुमार धंधानिया और विजय कुमार धंधानिया के घर पर छापा मारा। यह घर कोलकाता के 4, मिडलटन स्ट्रीट, पश्चिम बंगाल, पिन कोड 700071 पर स्थित है। इसके अलावा डी.सी. पॉल ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी पर भी तलाशी ली गई।

कंपनी का पता एसी 17, सॉल्ट लेक सिटी, सेक्टर-1, कोलकाता, पिन कोड 700064 है। ईडी ने कंपनी की डायरेक्टर कामलिनी पॉल के घर पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया। उनका निवास सीएफ 88, सेक्टर-1, सॉल्ट लेक, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन कोड 700064 पर है। साथ ही कंपनी की पूर्व डायरेक्टर शांति रंजन पॉल के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई। उनका पता ब्लॉक सीके-116, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पिन कोड 700091 है। जांचकर्ताओं का कहना है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों और गलत बोर्ड रिज़ॉल्यूशन का इस्तेमाल करके जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया। इससे मर्लिन ग्रुप को जमीन पर अवैध कब्जा करने में मदद मिली। इस मामले में पहले भी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एग्रीमेंट रद्द करने की मांग की गई थी। ईडी अब इन स्थानों से मिले दस्तावेजों, डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी चेन को उजागर करने की उम्मीद है। मर्लिन ग्रुप के प्रमोटर्स पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आईपीएल 2026 : मिलर ने आरसीबी से छीनी जीत, दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हराया

बेंगलुरु (एजेंसी)। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद केएल राहुल (34 गेंदों पर 57 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (47 गेंदों पर 60 रन) के अर्धशतकों के बाद अंतिम ओवरों में डेविड मिलर की 10 गेंदों पर 22 रन (एक चौका और 2 छक्के) की पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से शिकस्त दी।

सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट की 38 गेंद में 63 रन की आक्रामक पारी के बावजूद कैपिटल्स ने आरसीबी को 8 विकेट पर 175 रन पर रोकने के बाद 19.5 ओवर में चार विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। कैपिटल्स के लिए राहुल ने 34 गेंद की पारी में दो छक्के और चार चौके लगाए। टीम के 18 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद उन्होंने स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 44 गेंद में 69 रन की साझेदारी की। इसके बाद स्टब्स ने कप्तान अक्षर पटेल (26 रन पर रिटायर हर्ट) के साथ 35 गेंद में 47 रन की अटूट साझेदारी की।

अक्षर चोटिल होने के कारण 16वें ओवर में रिटायर हर्ट हो गए। स्टब्स ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद की नाबाद पारी में एक छक्का और चार चौके जड़े, जबकि डेविड मिलर (नाबाद 22) ने आखिरी ओवर में लगातार गेंदों पर दो छक्के और एक चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि कृणाल पंड्या ने 24 रन देकर एक विकेट हासिल किया। सॉल्ट ने अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए, लेकिन अक्षर पटेल (18 रन पर दो विकेट), कुलदीप यादव (32 रन पर दो विकेट) और लुंगी एनगिडी (39 रन पर दो विकेट) ने अन्य बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने का मौका नहीं दिया। मुकेश कुमार को भी एक सफलता मिली। सॉल्ट ने पहले विकेट के लिए विराट कोहली (19) के साथ 31 गेंद में 52 रन और दूसरे विकेट के लिए देवदत्त पडिक्कल (18) के साथ 29 गेंद में 47 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, लेकिन 11वें ओवर में उनके आउट होने के बाद टिम डेविड (17 गेंद में 26 रन) के अलावा कोई भी बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना सका।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को भुवनेश्वर कुमार ने अपने शुरुआती दो ओवर में तीन झटके दिए। उन्होंने पहले ओवर में ही पथुम निसांका (एक) को पगबाधा आउट किया और तीसरे ओवर में करुण नायर (पांच) और समीर रिजवी (दो) को पवेलियन भेजा। राहुल ने दूसरे छोर से जोश हेजलवुड का स्वागत छक्के से किया और चौथे ओवर में रसिक सलाम के खिलाफ मिड-ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 18 रन पर तीन विकेट गिरने के बावजूद पांचवें ओवर में हेजलवुड के खिलाफ स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाया और लगातार गेंदों पर चौके जड़कर दबाव को टीम पर हावी नहीं होने दिया। पावरप्ले में दिल्ली ने तीन विकेट पर 50 रन बना लिए।

स्टब्स संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि राहुल ने सुयश शर्मा के खिलाफ तीन चौके लगाकर रन गति को बनाए रखा और 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। कृणाल पंड्या ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल को आउट कर दिल्ली को बड़ा झटका दिया। विराट कोहली ने उनका शानदार कैच लपका।

अक्षर पटेल ने क्रीज़ पर आते ही कृणाल की बाउंसर गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका लगाया और फिर हेजलवुड तथा सलाम के खिलाफ भी चौके जड़े। अब तक रक्षात्मक खेल रहे स्टब्स ने सलाम की धीमी गेंद पर चौका लगाया और सुयश के खिलाफ शानदार स्ट्रेट ड्राइव पर चार रन बटोरे। टीम को आखिरी छह ओवर में 51 रन की जरूरत थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी कर बाउंड्री रोक दी। इसी बीच अक्षर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए। स्टब्स ने भुवनेश्वर के खिलाफ छक्का लगाकर 24 गेंद के बाउंड्री सूखे को खत्म किया तथा 41 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 19वें ओवर में सलाम का स्वागत चौके से किया, लेकिन इस युवा गेंदबाज ने अच्छी वापसी करते हुए ओवर से सिर्फ 10 रन दिए। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे और डेविड मिलर ने रोमारियो शेफर्ड की तीसरी और चौथी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर बराबर करने के बाद चौके के साथ टीम को जीत दिला दी। इससे पहले सॉल्ट ने शुरुआती ओवर में औकिब नबी के खिलाफ चौका जड़ा, जबकि कोहली ने मुकेश की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चार रन बटोरे।

इसके बाद अगले ओवर में भी उन्होंने लेग स्टंप के बाहर जाकर चौका मारा। संभलकर खेल रहे सॉल्ट ने नबी के खिलाफ पांचवें ओवर में दो चौके और पारी का पहला छक्का लगाकर 18 रन बटोरे, जिससे टीम का अर्धशतक पूरा हुआ। एनगिडी ने अगले ओवर में पहली ही गेंद पर कोहली को आउट कर पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी समाप्त की। सॉल्ट ने नटराजन का स्वागत चौके से किया, जबकि पडिक्कल ने भी इस गेंदबाज के खिलाफ छक्का लगाकर आक्रामक तेवर दिखाए।

सॉल्ट ने कुलदीप यादव के खिलाफ छक्का लगाकर 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। अक्षर ने अपने शुरुआती ओवर में ही पडिक्कल (18) को डेविड मिलर के हाथों कैच कराया, जबकि कुलदीप ने 11वें ओवर में छक्का खाने के बाद सॉल्ट को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच कराया। शानदार लय में चल रहे टिम डेविड ने एनगिडी के खिलाफ छक्का और चौका जड़ा, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार (आठ) मुकेश की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेटकीपर राहुल को कैच दे बैठे।

कुलदीप ने शेफर्ड (एक) को पगबाधा कर जल्दी पवेलियन भेज दिया। कृणाल (12) ने एनगिडी के खिलाफ छक्का लगाकर रनगति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आखिरी ओवर में रन आउट हो गए। जितेश शर्मा भी संघर्ष करते दिखे और उन्होंने 20 गेंद में 14 रन बनाए। आरसीबी ने आखिरी पांच ओवर में चार विकेट खोकर केवल 29 रन बनाए।

आरसीबी के लिए फिर अनलकी रही हरी जर्सी

दिल्ली कैपिटल्स ने यहां आरसीबी को छह विकेट से हरा दिया। आरसीबी को आठ विकेट पर 175 रन पर रोकने के बाद कैपिटल्स ने केएल राहुल (57 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (60 रन) के अर्धशतकों तथा डेविड मिलर की 10 गेंदों पर 22 रन की पारी की बदौलत 19.5 ओवर में चार विकेट पर 179 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह आरसीबी के लिए हरी जर्सी एक बार फिर अनलकी रही। हरी जर्सी में आरसीबी का रिकॉर्ड खराब रहा है क्योंकि 15 मैचों में केवल 5 जीत मिली है। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े। कोहली ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने 38 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। टिम डेविड ने 26 रन बनाए। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए, जबकि मुकेश कुमार को एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 19.5 ओवर में चार विकेट पर 179 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ट्रिस्टन स्टब्स 60 रन और डेविड मिलर 22 रन बनाकर नाबाद रहे। भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट लिए और कृणाल पंड्या को एक सफलता मिली।

आईपीएल 2026: धोनी ने ग्राउंड्समैन के साथ खिंचवाई तस्वीरें, वायरल हो रहा वीडियो

हैदराबाद (एजेंसी)। चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर मैदान के बाहर अपने दिल छू लेने वाले अंदाज से सबका दिल जीत लिया। शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले से पहले उन्हें राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत करते और तस्वीरें खिंचवाते देखा गया। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में धोनी को ग्राउंड्समैन के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते, मुस्कुराते और तस्वीरों के लिए पोज देते देखा जा सकता है। यह उनके विनम्र स्वभाव और खेल में अक्सर गुमनाम रहने वाले इन योगदानकर्ताओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है।

इस बीच धोनी ने आईपीएल 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है क्योंकि अभ्यास सत्र के दौरान उन्हें पिंडली में चोट लग गई थी। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से पहले, इस सीजन में पहली बार उन्होंने टीम के साथ यात्रा की है। हाल ही में धोनी को नेट्स में बल्लेबाजी करते देखा गया, जहां वे गेंद को साफ-सुथरे ढंग से हिट कर रहे थे और आसानी से बाउंड्री के पार भी भेज रहे थे।

चेन्नई सुपर किंग्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वे अच्छी लय में दिख रहे थे, जिससे प्रशंसकों के बीच उत्साह और भी बढ़ गया। हालांकि अभी भी 45 वर्षीय धोनी शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा नहीं बने। धोनी आईपीएल के सबसे भरोसेमंद योगदानकर्ताओं में से एक बने हुए हैं। 278 मैचों में उन्होंने 242 पारियों में 5,439 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा है। उनके रिकॉर्ड में 24 अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 84 रन है। इस प्रदर्शन के साथ वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में छठे स्थान पर हैं।

भारत में शुरू होने जा रही फ्लाइंग टैक्सी, इंडिगो ने इस देसी स्टार्टअप पर लगाया बड़ा दांव

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोचिए, आप सुबह घर से निकलें और 100 किलोमीटर दूर किसी शहर में अपनी मीटिंग के लिए सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाएं। न कोई ट्रैफिक जाम, न रेड लाइट और न ही ट्रेन का लंबा इंतजार। सुनने में यह किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन अब यह भारत में हकीकत बनने जा रहा है। देश में 30 से 300 किलोमीटर की 'मिडिल डिस्टेंस' यात्रा को आसान बनाने के लिए देसी स्टार्टअप 'सरला एविएशन' और दिग्गज एयरलाइन कंपनी 'इंडिगो' ने हाथ मिला लिया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में एक नया एयर टैक्सी नेटवर्क तैयार कर रही हैं, जो सड़क और आसमान के बीच की दूरी को मिटाकर सफर का पूरा अनुभव बदल देगा।

भारत में सड़क और रेलवे का बेहतरीन जाल होने के बावजूद 100-200 किलोमीटर की यात्रा के लिए लोगों को अक्सर भारी ट्रैफिक और घंटों की देरी का सामना करना पड़ता है। इसी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए इंडिगो वेंचर्स ने सरला एविएशन में 10 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया है। इस निवेश को भारत के पहले बड़े एयर टैक्सी नेटवर्क की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सरला एविएशन का यह फंडिंग राउंड एक्सेल और निखिल कामथ के नेतृत्व में पूरा हुआ है। इंडिगो के पास रोजाना 2000 से ज्यादा उड़ानों और 85 एयरपोर्ट का मजबूत नेटवर्क है, जो इस प्रोजेक्ट को तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर पर बड़ी ताकत देगा।

सरला एविएशन अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है। इसे हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भी पेश किया गया था। इस 6-सीटर फ्लाइंग टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उड़ान भरने या उतरने के लिए किसी लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती। यह बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर

की तरह अपनी जगह से ही सीधे टेक-ऑफ कर सकती है और एक ही पॉइंट पर लैंड कर सकती है। बैटरी और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने वाले ये एयरक्राफ्ट बेहद शांत होते हैं और प्रदूषण भी ना के बराबर फैलाते हैं। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इस एयर टैक्सी की ग्राउंड टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक शुरू कर दी है।

इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कई व्यस्त रूटों पर सफर का समय चमत्कारी रूप से कम हो जाएगा। सरला एविएशन ने कुछ प्रमुख शहरों के भारी ट्रैफिक वाले रूटों का एक खाका पेश किया है, जिससे यह साफ होता है कि इस एयर टैक्सी के आने से यात्रा में कितना बड़ा बदलाव आएगा।

इस आधुनिक तकनीक के जरिए बेंगलुरु एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक का 92 मिनट का सफर अब मात्र 10 मिनट में पूरा होगा, वहीं मुंबई के जुहू से पुणे पहुँचने में लगने वाले 219 मिनट घटकर केवल 30 मिनट रह जाएंगे। इसी तरह, दिल्ली-एनसीआर के व्यस्त रूट गुरुग्राम से नोएडा की दूरी 121 मिनट के बजाय अब महज 15 मिनट में तय की जा सकेगी। पर्यटन स्थलों पर भी इसका बड़ा असर दिखेगा, जहाँ मोपा एयरपोर्ट से साउथ गोवा जाने में अब 144 मिनट के बदले सिर्फ 21 मिनट लगेंगे और कोच्चि से मुन्नार का 196 मिनट का लंबा पहाड़ी रास्ता केवल 10 मिनट की हवाई यात्रा में सिमट जाएगा।

आरबीआई में निकली जूनियर इंजीनियर की भर्ती, 11 पदों के लिए आवेदन शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश का एकमात्र केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) के विभिन्न 11 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आरबीआई ने जेई के जिन 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 7 और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 4 पद शामिल हैं। आरबीआई की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया गुरुवार, 16 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 मई निर्धारित की गई है।

ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित इंजीनियरिंग विषय में न्यूनतम 65त्न अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और तय सालों का अनुभव होना भी अनिवार्य है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

जीरो टैक्स होने पर भी आईटीआर भरना क्यों है जरूरी जानें 5 बड़े फायदे

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में कई ऐसे करदाता हैं जिनकी आय टैक्स के दायरे से नीचे रह सकती है। इसका कारण सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाली छूट, कटौतियां या पार्ट-टाइम काम, फ्रीलांसिंग और डिविडेंड जैसी कम आय हो सकती है। ऐसे में, एक आम सवाल उठता है कि जब टैक्स देनदारी शून्य है तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना जरूरी है? इसका जवाब है—हां, कई मामलों में 'निल आईटीआर' फाइल करना फायदेमंद और समझदारी भरा कदम होता है। जानकारों का कहना है कि असल में आईटीआर फाइल करना सिर्फ टैक्स चुकाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी सालाना आय का एक आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, जो आयकर विभाग के पास दर्ज रहता है। भले ही आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो, फिर भी आईटीआर भरने से आपकी वित्तीय हिस्ट्री साफ और व्यवस्थित रहती है, जो आगे चलकर कई कामों में मदद करती है।

केंद्रीय कर्मचारियों का 60% हुआ डीए, सैलरी में बढ़ोतरी और एरियर की बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों की आय में सीधी बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए की नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को जनवरी से अप्रैल तक के चार महीने का एरियर भी मिलेगा, जो अप्रैल की सैलरी के साथ एकमुश्त दिया जाएगा। एरियर मिलने से कर्मचारियों के हाथ में एक साथ बड़ी राशि आएगी, जिससे बाजार में खर्च और मांग बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इस फैसले का सीधा लाभ देश के लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि 68.27 लाख पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा पेंशन पर निर्भर होता है और महंगाई बढ़ने के साथ उनका खर्च भी बढ़ जाता है।

डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि भले ही कम दिखाई दे, लेकिन इसका मासिक आय पर सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो पहले उसे 58 प्रतिशत की दर से 17,400 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब 60 प्रतिशत होने पर उसे 18,000 रुपये मिलेंगे, यानी हर महीने 600 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर देखें तो यह राशि 7,200 रुपये तक पहुंच जाती है, और एरियर जोड़ने पर यह रकम और अधिक हो जाती है। इसी तरह 20,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को पहले 11,600 रुपये डीए मिल रहा था, जो अब बढ़कर 12,000 रुपये हो जाएगा। इससे हर महीने 400 रुपये और सालाना 4,800 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी और भी अधिक प्रभाव डालती है क्योंकि डीए बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। महंगाई भत्ता बढ़ाने का उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाना होता है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई-आईडब्ल्यू के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, उसी के अनुसार डीए में संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में बदलाव करती है। आमतौर पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती हैं, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में कई राज्यों के कर्मचारी भी इसी तरह की खुशखबरी पा सकते हैं। डीए बढ़ोतरी के साथ ही अब कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग की चर्चा फिर तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन संरचना को समय के साथ अपडेट करने की जरूरत है और न्यूनतम वेतन में हर साल कम से कम 6 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अलावा बेसिक सैलरी में भी बड़ा इजाफा करने की मांग उठाई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक समयसीमा घोषित नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुल मिलाकर डीए में यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आई है। एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी मिलने से कर्मचारियों के बजट को मजबूती मिलेगी और महंगाई के दौर में आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह फैसला कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है।

संपादकीय

नहीं बनी सहमति

महिला आरक्षण देने के तरीके और परिसीमन पर सहमति न बनना आश्चर्यजनक नहीं, पर चिंताजनक जरूर है। संविधान में संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए, पर यह अभी केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास नहीं है। सरकार बहुत प्रयास के बावजूद तीन विधेयकों को पारित कराने में नाकाम रही है। यह बात बहुत मुखरता से सिद्ध हुई है कि विपक्ष के नेताओं में सत्ता पक्ष के प्रति विश्वास की भारी कमी है। सत्ता पक्ष के प्रति एकजुट विपक्ष की तल्खी गौर करने लायक है। बहुत कम अवसर आए हैं, जब विपक्ष में ऐसी एकता दिखाई पड़ी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के भाषण में वर्तमान सत्ता या भाजपा विरोध का जो स्तर देखा गया है, उसमें सहमति बनाने की राह कतई आसान नहीं है। यह लोकतंत्र और संविधान का एक सशक्त पहलू है कि अगर किसी सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, तो वह संविधान संशोधन नहीं कर सकती। भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन लोकसभा में महज 298 सीटों तक सिमट गया। वर्ष 1976 में परिसीमन को संविधान संशोधन से रोका गया था। तब से नए परिसीमन का इंतजार है और अभी न जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा?

अब आगे क्या होगा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस विशेष सत्र में क्या हुआ है? पहली बात, इस विशेष सत्र में विपक्ष की ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती सामने आई हैं। दूसरी बात, दक्षिण के राज्यों और दलों की दलीलों को जिस तरह का समर्थन उत्तर के राज्यों के नेताओं से मिला है, वह उल्लेखनीय है। उत्तर के नेताओं ने फिर सिद्ध किया है कि उन्हें दक्षिण के लोगों की पूरी परवाह है। तीसरी बात, चूंकि राजनीतिक दल अपने स्तर पर पिछड़ी, दलित, ओबीसी, मुस्लिम महिलाओं को पर्याप्त चुनावी टिकट देने में नाकाम हो रहे हैं, तो अब उनकी कोशिश है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण संबंधी कानून में ही यह प्रावधान कर दिया जाए। मतलब, सरकार आज करे या कल, उसे आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान लीजिए, ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई, तो भी यह राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाएगा। आरक्षण से अटूट रूप से जुड़ चुकी भारतीय राजनीति की विवशता से हर सियासी दल को गुजरना पड़ेगा।

विशेष सत्र में यह साबित हुआ कि परिसीमन का काम भारत में आसान नहीं है। 1976 के बाद से 2026 तक देश को परिसीमन का इंतजार है। संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि आबादी के हिसाब से विधायिका में सीटों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन आबादी 50 करोड़ से 140 करोड़ पर पहुंच गई है।

“मीडिया की ताकत आज सर्वव्यापी है और कई मायनों में सर्वग्रासी भी। ऐसे में विकास के सवालों और उसके लोकव्यापीकरण में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो उठी है। यह एक ऐसा समय है, जबकि विकास और सुशासन के सवालों पर हमारी राजनीति में बात होने लगी है, तब मीडिया में यह चर्चाएं न हों यह संभव नहीं है। समाज विकास की प्रक्रिया और उसकी आकांक्षाएं मीडिया में दर्ज हों, ऐसी उम्मीद की जाती है। इन विषयों की रिपोर्टिंग के लिए तमाम पत्रकार आगे आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी विकास की पत्रकारिता को एक नई नजर से देखा जा रहा है। भारत में विकास की पत्रकारिता और उसके सवालों से जूझने के लिए पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार है, किंतु मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा इन विषयों को तरजीह न दिए जाने के कारण निराशा ही हाथ लगती है। संकट पत्रकारों की ओर से नहीं, मीडिया संस्थानों और प्रबंधकों की ओर से है। विकास का मुद्दा क्या सिर्फ सरकारी विज्ञापनों का विषय है, सरकारी मीडिया का विषय है, या यह समाज में हो रहे नवाचारों का भी विषय है। विकास पत्रकारिता को पाठ्यक्रम के साथ मीडिया कर्म का भी हिस्सा होना चाहिए।”

विकास और सुशासन के मुद्दों पर भी काम करे मीडिया

भारत जैसे विविधता और बहुलता भरे समाज में सभी उम्मीदों, सपनों और बदलावों को रेखांकित कर पाना कठिन है। क्योंकि विकास के अनेक तल हैं और देश में समाज की रचना भी बहुस्तरीय है, देश में कहावत प्रचलित है 'चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर वाणी' , इसलिए किसी राज्य को भी एक ही पैमाने से नहीं नापा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश में एक तरफ समृद्ध मालवा है, तो दूसरी और झाबुआ जैसे इलाके भी हैं। एक तरफ इंदौर की चमक है, तो दूसरी ओर अलीराजपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ है, तो भिलाई भी है। ऐसे में पत्रकारों या विकास के सवालों पर लिखने वालों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह विकास की भूमिका भी यहां विस्तृत और परिवर्तित हो जाती है। हम देखें तो 1950 के पहले आर्थिक विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। किंतु 1950 के बाद की चिंताएं अलग हो गयी। बाद के दिनों में सामाजिक विकास को एक बड़ा कारक माना जाने लगा है। सामाजिक न्याय से लेकर स्थाई विकास के सवाल अब बड़े हो गए हैं। यहां तक कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें भी हमारे सामने हैं।

एक समय में विकसित और विकासशील देशों की बहसें भी हमने सुनीं जिनमें मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट एक अलग तरह से बात करती हुयी नजर आती है, जिनमें कुछ सवाल आज भी मौजू हैं। नियंत्रित मीडिया से मीडिया के चौतरफा विकास का समय भी आया जिसमें कुछ भी छिपाना और दबाना असंभव सा हो गया। कई बार यह भी लगता रहा कि विकास का सवाल सिर्फ सरकारी माध्यमों (मीडिया) के लिए ही महत्व का है, बाकी माध्यमों का अपना एजेंडा और राय अलग है। यहां यह भी देखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन(संचार) सिर्फ सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं है। बल्कि पक्षधरता के साथ, न्याय के लिए खड़ा होना भी है। जन को ताकतवर बनाना भी है। अवसर की समानता की अवधारणा को प्रचारित और स्थापित करना भी है।

विकेन्द्रीकरण ने विकास के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। जिनके भी ठोस और वाजिब हल हमें ढूंढने चाहिए। जैसे पंचायती राज में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। सत्ता इसके चलते पंचायतों तक पहुंची, पर सवाल यह है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है? क्या संसदीय राजनीति और चुनावों की तमाम बुराईयां हमारी पंचायतों तक नहीं पहुंच गयी? वहीं हम मीडिया को देखें तो उसका भी विस्तार हुआ है। व्यापकता बढ़ी है, पहुंच भी बढ़ी है। पर सवाल यह है कि क्या मीडिया में संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता और विविधता को आदर देने की उसकी भावना भी बढ़ी है, तो शायद उत्तर नकारात्मक ही हो। तीनों तंत्रों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) से निराश लोग मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं। कई अर्थों में सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण दिखता है, किंतु मीडिया धीरे-धीरे केन्द्रीकरण का शिकार हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्रास मीडिया ओनरशिप के बारे में भी भारत जैसे देश सोचें। ताकि मीडिया के एकाधिकार के खतरों से बचा जा सके। इसके साथ ही प्रेस कौंसिल जैसी नख-दंत हीन संस्था के अधिकारों और क्षेत्राधिकार में बदलाव करते हुए उसे मीडिया कौंसिल में बदला जाना जरूरी है ताकि वह आज के प्रभावी मीडिया को भी अपनी चर्चा में ले सके।

हम जिस संकट से दो चार हैं, वह यह है कि सूचनाएं बढ़ गई हैं और खबरें घट गई हैं। अखबारों के पन्ने बढ़ गए हैं, किंतु इनसे आम-आदमी गायब है। चैनल अब चौबीस घंटे कुछ बोलते हैं, पर उनमें विकास और जनता के सवालों की जगह बहुत कम है। जबकि विकास की पत्रकारिता की मुक्ति इसमें है कि जो लोग मीडिया तक नहीं पहुंच सकते, मीडिया उन तक पहुंचे। उनका दर्द सुने। अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबरों की ओर जाएं। हमारी राजनीति बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है किंतु हमारे मीडिया के सोचने और अभिव्यक्त करने की शैली उस तुलना में नहीं बदली जैसी बदलनी चाहिए। आज यह मान्यता बन चुकी है कि विकास भारतीय मीडिया की प्राथमिकता नहीं है, शायद समाज भी उसकी प्राथमिकता नहीं है। हमारे नागरबोध ने मीडिया को समाज से बड़ा बना दिया है। किंतु यह तय मानिए कि कोई भी मीडिया, कोई भी राजनीति और कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। 18 से 25 साल और 18 से 35 साल के युवाओं के बीच बाजार खोज रहे मीडिया की चिताएं अलग हो सकती हैं किंतु समाज की चिताएं कुछ भिन्न हैं। वे ही वास्तविक चिंताएं हैं। मीडिया अगर इन चिंताओं से अलग व्यवहार कर रहा है तो वह अपने अस्तित्व पर संकट स्वयं रच है। विश्वसनीयता और प्रामणिकता के संकट तो उसके साथ संयुक्त हैं ही। मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह सोचने का सही समय है कि जब सारा देश विकास और सुशासन के सवालों पर गंभीर हो रहा है, उसमें अपने शासकों से जवाब मांगने की हिम्मत आ रही है, तो हमारा मुख्यधारा का मीडिया क्या कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के सामने आज उपस्थिति हैं, अगर इन सवालों के हल हमने आज नहीं तलाशे तो कल बहुत देर हो जाएगी।

बिंदी Ban, हिजाब Allowed, Lenskart के वायरल डॉक्यूमेंट पर क्या विवाद चल रहा है?

अभी टाटा कंसलटेंसी सर्विज यानी टीसीएस से जुड़ा विवाद पूरी तरह थमा भी नहीं था कि एक और बड़ी कंपनी को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आने लगी है। इस बार मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है बल्कि उस सवाल का है जो हम सबके वर्क प्लेस से सीधे जुड़ा है। मामला है ड्रेस कोड पॉलिसी का। क्या एक कंपनी यह तय कर सकती है कि आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे दिखाएं? या अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को दिखाना जरूरी है भी? क्या ऑफिस में आपकी धार्मिक पहचान और उससे जुड़े पर्सनल बिलीफ आपकी अपनी चॉइस होगी या कंपनी की पॉलिसी उसे तय करेगी? तमाम विवाद चश्मे बनाने वाली पॉपुलर कंपनी लेंस कार्ड से जुड़ा है। क्या है लेंस कार्ड से जुड़ी कंट्रोवर्सी और क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा?

दरअसल, लेंस कार्ड की 27 पन्नों की गाइड बुक में तमाम ऐसे नियम है जिन्हें लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। वैसे लेंस कार्ड के सीईओ पीयूष बंसल ने इन नियमों को पुराना बताया है। लेकिन ट्रोल्स का कहना है कि गाइडलाइन पुरानी हो या फिर नई हो है तो आपकी ही। पहले जानेंगे कि किन नियमों को लेकर विवाद है और फिर जानेंगे कि पीयूष बंसल का क्या कहना है।

शुरुआत एक एक्स पोस्ट से हुई। 15 अप्रैल को शेफाली वैद नाम की एक्स यूजर ने लेंस कार्ड को टैग करते हुए कुछ फोटो शेयर की। इन तस्वीरों को लेंस कार्ट स्टाफ यूनिफार्म एंड ग्रूमिंग गाइड का हिस्सा बताया जा रहा है। तस्वीर में दिखाए गए नियम के हिसाब से कंपनी की वर्कर्स एक पर्टिकुलर लेंथ का हिजाब पहन सकती हैं। लेकिन किसी भी कलर की बिंदी, स्टोन या फिर कलावा नहीं पहन सकती। सिंदूर को लेकर भी नियम बताया गया कि इसे मिनिमम लगाना है और इस तरह से लगाना है कि माथे पर नहीं आए। इस तरह के और भी कई सारे नियमों का जिक्र किया गया। इस फोटो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा मैं नियमों को कंफर्म कर रही हूं। पीयूष बंसल अपने वर्कर्स को यही बताते हैं कि हिजाब ओके है लेकिन बिंदी तिलक क्या कलावा ओके नहीं है। यह ऐसी कंपनी है जो हिंदू बहुल देश भारत में है। जिसके अधिकतर वर्कर्स और कस्टमर हिंदू हैं। आप इस पर क्या कहेंगे?

वायरल डॉक्यूमेंट में कई तरह के ड्रेस कोड निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि अगर कोई कर्मचारी पगड़ी पहनता है तो उसका रंग काला होना चाहिए। इसी तरह हिजाब पहनने की अनुमति थी लेकिन उसके लिए भी काले रंग की शर्त रखी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि हिजाब का कवरेज सीमित हो। वहीं स्टोर में बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। विज़िबल टैटू से बचने की सलाह दी गई थी ताकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इसके अलावा मेहंदी लगाने पर भी रोक थी और अगर किसी खास मौके पर लगानी हो तो पहले से अनुमति लेनी होगी और वह भी सीमित समय के लिए। सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा वो था जिसमें धार्मिक प्रतीकों को लेकर निर्देश दिए गए थे। जैसे कि तिलक, बिंदी या किसी भी तरह का धार्मिक स्टीकर पहनने की अनुमति नहीं थी।

यह नियम लेंस कार्ट स्टाइल गाइड के पेज नंबर 11 में लिखा है। इस फोटो को शेयर करते हुए एक और यूजर ने लिखा, क्या सच में यह हिंदू बहुसंख्यक या सेकुलर देश है? हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है और अल्पसंख्यक मुसलमानों को वर्क प्लेस में अपनी धार्मिक पहचान का पालन करने की इजाजत दी जाती है। लेंस कार्ट यह रवैया हिंदू संस्कृति और परंपराओं को टारगेट कर रहा है। ऐसे ही और सारे कमेंट्स आए तो पीयूष बंसल ने जवाब भी दिया। पीयूष ने लिखा कि हर साल नियमों में बदलाव होता है। हमारी कंपनी में अलग-अलग धर्म के हजारों लोग काम करते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसके आगे पीयूष ने जो लिखा हम शब्दशा बता देते हैं। पीयूष ने लिखा, मैंने देखा है कि लेंस कार्ड का गलत पॉलिसी डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह डॉक्यूमेंट हमारे वर्तमान दिशा निर्देशों को नहीं दिखाता। हमारी पॉलिसी में धार्मिक अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं है। इसमें बिंदी और तिलक भी शामिल है। हम नियमित रूप से अपने दिशा निर्देशों को रिव्यू करते रहते हैं। हमारी ग्रूमिंग पॉलिसी समय के साथ विकसित हुई है और इसके पुराने नियम आज हमारी पहचान को सही ढंग से नहीं दिखाते हैं। आपको जो कंफ्यूजन हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। एक कंपनी के रूप में हम लगातार सीखते और आगे बढ़ते हैं। हमारी भाषा या नीतियों में खामियों को दूर किया गया है और आगे भी किया जाता रहेगा। भारत में हमारे हजारों कर्मचारी जो हमारे स्टोर्स में अपने धर्म और संस्कृति को गर्व से दिखाते हैं। यही लेंस कार्ड है। लेंस कार्ड भारत में बना था भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए। हमारे लोगों की हर परंपरा हमारी कंपनी की पहचान का हिस्सा है। मैं कभी भी इसे खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। यूजर ने पीयूष के जवाब पर क्रॉस क्वेश्चन किया। लिखा कि सॉरी, इस सफाई का कोई मतलब नहीं है। ये डॉक्यूमेंट फरवरी 2026 का है। अगर ये नियम आज की गाइडलाइन को नहीं दिखाते तो प्लीज नए वाले शेयर कर दीजिए। भले ही यह पुराना डॉक्यूमेंट हो तो उस समय भी इसे क्यों स्वीकार किया जाता था। हिजाब और पगड़ी की इजाजत थी लेकिन बिंदी, सिंदूर और कलावा की नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक था? अपने वकील से कहिए इस तरह का कमजोर स्पष्टीकरण तैयार करने के बजाय बेहतर तरीके से काम करें। इसके बाद इस खबर को रिकॉर्ड किए जाने तक पीयूष का कोई जवाब सामने नहीं आया।

चार धाम यात्रा में आस्था और पर्यावरण का तालमेल जरूरी

चार धाम यात्रा की रविवार 19 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे और 22 अप्रैल से केदारनाथ व 23 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम श्रद्धालु जा सकेंगे। चूंकि सनातन धर्म में इस यात्रा का काफी महत्व है, इसलिए अच्छी-खासी संख्या में श्रद्धालु यहां आते रहते हैं।

वर्ष 2024 में 48 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की, जबकि 2025 में यह संख्या 6.4 प्रतिशत बढ़कर 51 लाख से अधिक हो गई। हालांकि, 2023 में दर्ज 56,16,653 श्रद्धालुओं की तुलना में 2025 का आंकड़ा कम था, पर यह संकेत है कि संख्या में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है और इसे सफलता या विफलता का एकमात्र पैमाना नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय, हमें यह समझना चाहिए कि यहां कितनी संख्या सुरक्षा, सुगमता व पर्यावरणीय दृष्टि से संभाली जा सकती है। पाथवेज टु पिलग्रिमेज : डाटा इनसाइट्स, चैलेंजेज ऐंड ऑपर्च्युनिटीज रिपोर्ट साल 2025 की यात्रा की पृष्ठभूमि में ही मैंने तैयार की है। यह रिपोर्ट गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब धामों में श्रद्धालुओं के रुझानों का समग्र चित्र पेश करती है, जिसमें हितधारकों के दृष्टिकोण और सुरक्षा व प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों के सुझाव शामिल किए गए हैं।

इस अध्ययन में हमने वर्ष 2025 में उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन और आपदा के जो पांच प्रमुख रुझान देखे, वे एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। पहला, बुनियादी ढांचा-जनित आपदा जोखिम, जहां सड़कें, सुरंगें और अन्य निर्माण-गतिविधियां भूस्खलन और भू-धंसाव के खतरे बढ़ाती हैं।

दूसरा, ग्लेशियर झीलों में तेजी से हो रहे बदलाव, जो याद दिलाते हैं कि हमारी तैयारी अब भी इस बदलते जोखिम के मुकाबले अपर्याप्त है। तीसरा, शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में आपदाओं का उभरना, जो दर्शाता है कि अब जोखिम केवल दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रहा। चौथा, प्रशासनिक देरी और जवाबदेही की कमी, जो आपदा के दुष्प्रभावों को गति देती हैं और पांचवां, पर्यटकों का बढ़ता दबाव, जो आर्थिक मौके तो देते हैं, पर पारिस्थितिकीय संतुलन पर भारी बोझ भी डालते हैं। वर्ष 2025 के इस विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। उस साल पांचों धामों में कई दिनों तक शून्य या अत्यंत कम श्रद्धालु-संख्या दर्ज की गई, जो आपदा, भूस्खलन व बुनियादी ढांचे की कमजोरियों का परिणाम है।

‘‘महिलाओं को हक देने में और देरी सही नहीं’’

भारतीय संसद तीन दिवसीय सत्र में एक ऐसे युगांतकारी विधेयक पर चर्चा कर रही है, जो हमारे विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल सीटों का आरक्षण नहीं है, यह उन करोड़ों महिलाओं के सपनों की उड़ान है, जो भारत को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त बनाने की भूमिका में अपनी आहुति देना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां नारी केवल 'सहायक' नहीं, बल्कि '2047 तक विकसित भारत' के निर्माण की 'मार्गदर्शक' होगी।

नारी शक्ति के लिए आरक्षण का मुद्दा लगभग तीन दशकों तक संसद में लटका रहा। कई बार इसके लिए प्रयास हुए, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और अकारण विरोध के कारण यह बिल तब कानून नहीं बन पाया। अब जब यह हकीकत बनने जा रहा है, तो विपक्ष को 'केवल विरोध के लिए विरोध करने' के बजाय एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्वीकार कर राष्ट्र-निर्माण में अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए, ताकि उसके ऊपर का यह 'दाग' मिटाया जा सके कि विपक्ष हर उस कदम का विरोध करता है, जिससे देश-समाज का भला होता है या नारी शक्ति का सशक्तीकरण होता है। दुनिया के कई विकसित देशों के नीति-निर्धारण में स्त्रियों की भागीदारी बहुत अधिक है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक न रहे। विपक्ष का समर्थन यह संदेश देगा कि भारत का संपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व लैंगिक समानता के प्रति एकजुट है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की लोकतांत्रिक छवि और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह केवल एक बिल नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान की वह उद्घोषणा है, जिसे साकार करने का सपना हम दशकों से देख रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, उनके सशक्तीकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। महिलाओं के जीवन के हरेक चरण में उनके सशक्तीकरण के लिए योजनाओं का एक व्यापक तंत्र तैयार किया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप योजना, स्टैंड-अप योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, महिला स्वयं सहायता समूह आदि योजनाओं ने देश की स्त्रियों को न केवल गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया है, बल्कि देश की प्रगति में उन्हें आर्थिक ताकत भी बनाया है। यह हमारे प्रधानमंत्री ही हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 'ट्रिपल तलाक' के दंश से मुक्ति दिलाकर सम्मानपूर्ण जीवन का हक दिया है।

ये सारी योजनाएं महिला सशक्तीकरण के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का ही प्रमाण हैं। अब नीति-निर्धारण में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए प्रधानमंत्री ये तीनों विधेयक लेकर आए हैं। यह केवल आश्वासन नहीं है, बल्कि उनकी स्पष्ट दृष्टि है कि वर्ष 2029 से संसदीय प्रणाली में महिलाओं की 33 प्रतिशत मौजूदगी रहे, वे सशक्त हों, नीति-निर्धारण में उनकी निर्णायक भूमिका हो और वे देश की मुखर आवाज बनें।

अब तक विपक्ष प्रश्न उठाता रहा है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए परिसीमन तक का इंतजार क्यों किया जाए, उन्हें आरक्षण तुरंत दीजिए। साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के समय उनकी यही मांग थी। हालांकि, तब सात-आठ महीने के भीतर ही लोकसभा चुनाव होने वाले थे और इतनी जल्दी आरक्षण के लिए कानून बनाना संभव नहीं था। अब अगर हमने इस समय नारी शक्ति को अधिकार नहीं दिए, तो बहुत देर हो जाएगी और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है, अगर हम इस समय इन तीनों विधेयक का विरोध करते हैं, तो आधी आबादी को कभी विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि उनके अधिकारों को हम सम्मान देना चाहते हैं। भारत की बेटियां आज केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि 'नेतृत्वकर्ता' बन रही हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। आज हमारी बेटियां न केवल सफलतापूर्वक कंपनियां चला रही हैं, बल्कि फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। खेल से लेकर कला तक और अर्थव्यवस्था से लेकर डिफेंस तक महिलाएं आज हर जगह परचम लहरा रही हैं। यह सूची अनंत है, जो प्रमाणित करती है कि नारी शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में है। संसद में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने का निर्णय 'वैदिक गरिमा' और 'आधुनिक प्रगति' का सुंदर संगम है। इसमें 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' की पवित्र भावना शामिल है। यह विधेयक उन करोड़ों माताओं-बहनों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने परिवार और समाज के निर्माण में स्वयं को खपा दिया। इस बदलाव का क्रांतिकारी प्रभाव हमारे ग्रामीण भारत पर पड़ेगा, जहां महिलाएं अब नेतृत्वकारी भूमिका में उभरेंगी। यह सक्रिय भागीदारी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा वातावरण बनाएगी, जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखेंगी, बल्कि उन्हें साकार करने का सामर्थ्य और वैधानिक अधिकार भी रखेंगी।

जब किसी चीज में आपकी आस्था होती है तो वो आपकी आत्मा को टच कर जाता है: नुसरत

मैंने 16 शुक्रवार का व्रत भी रखा हैज्मुस्लिम होकर मंदिर जाने पर बोलीं नुसरत भरूचा

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा से अंक ज्योतिष को लेकर सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही मंदिर जाती रही हैं. इसके अलावा वो 16 शुक्रवार का व्रत भी रख चुकी हैं. उन्होंने इस बारे में भी बताया कि वो केदारनाथ और बद्रीनाथ भी गई हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष पर यकीन करती हैं. इसलिए उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव किया था. उन्होंने Nushrat Bharucha से अपना नाम Nushrratt Bharuccha कर लिया. हाल ही में नुसरत से सवाल हुआ कि उनका ताल्लुक मुस्लिम परिवार से हैं, तो क्या घर में उनसे अंक ज्योतिष को लेकर सवाल नहीं हुआ था. इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब देते हुए नुसरत ने कहा, बचपन से ही मैं मंदिर जाती रही हूं, गुरुद्वारा और चर्च भी जाती हूं. मैंने तो 16 शुक्रवार को व्रत भी रखा था. इंटरव्यू में नुसरत से ये भी सवाल हुआ कि वो केदारनाथ क्यों गई थीं. नुसरत ने कहा, केदारनाथ और बद्रीनाथ, मेरा बहुत मन था कि मैं दोनों जगह पर जाऊं. मैं वहां दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी. मैं वहां माथा टेकना चाहती थी, आशीर्वाद लेना चाहती थी और खुद को खुशनसीब महसूस करना चाहती थी.नुसरत ने आगे कहा, जब किसी चीज में आपकी आस्था होती है तो वो आपकी आत्मा को टच कर जाता है, उस चीज को बयां नहीं किया जा सकता है. मैं जब केदारनाथ गई थी तो मैं वहां सिर्फ बैठना चाहती थी. मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ बैठना था.नुसरत ने आगे कहा, जब किसी चीज में आपकी आस्था होती है तो वो आपकी आत्मा को टच कर जाता है, उस चीज को बयां नहीं किया जा सकता है. मैं जब केदारनाथ गई थी तो मैं वहां सिर्फ बैठना चाहती थी।

तलाक के बाद पहली बार अपने रिश्ते को लेकर बोलीं हंसिका मोटवानी, कहा- कोई पछतावा नहीं

एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी काफी दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में चल रही हैं. एक्ट्रेस की शादी और तलाक को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब उन्होंने पहली बार खुलकर अपनी बात सभी के सामने रखी है. हंसिका ने अपने टूटे रिश्ते और शादी खत्म होने पर बात करते हुए कहा कि जिंदगी में कभी-कभी गलत ट्रेन में चढ़ जाने से बेहतर है कि सही समय पर उतर जाया जाए. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर उनका तलाक चर्चा का विषय बन गया है और फैंस भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनकी शादी में क्या हुआ.

हंसिका मोटवानी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद ही वो बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का जाना माना नाम बन गईं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा काफी बढ़ गई. दरअसल, हंसिका मोटवानी और बिजनेसमैन सोहेल खटूरिया की शादी कुछ साल पहले धूमधाम से हुई थी, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं. बताया जा रहा था कि दोनों लंबे समय से अलग रह रहे थे और आखिरकार आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया.

हंसिका मोटवानी और सोहेल खटूरिया का मार्च 2026 में तलाक फाइनल हुआ और इसके बाद हंसिका ने इस पूरे मामले पर अब अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें इस फैसले का कोई पछतावा नहीं है और वो अब अपने जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दे रही हैं. हाल ही में हंसिका एक पॉडकास्ट में शामिल हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी थी.

परिवार का मुझे पूरा साथ मिला

एक्ट्रेस ने कहा, 'लोगों को क्लिकबेट चाहिए था, उन्हें मिल गया, उन्हें हेडलाइन चाहिए थी, वो भी मिल गई. मैंने कभी सफाई नहीं दी और ना ही दूंगी, क्योंकि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई पछतावा नहीं है. अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हों, तो तकलीफ सहने से बेहतर है कि समय रहते उतर जाएं. मेरे परिवार का मुझे पूरा साथ मिला है. मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं जहां हूं बहुत खुश हूं।'

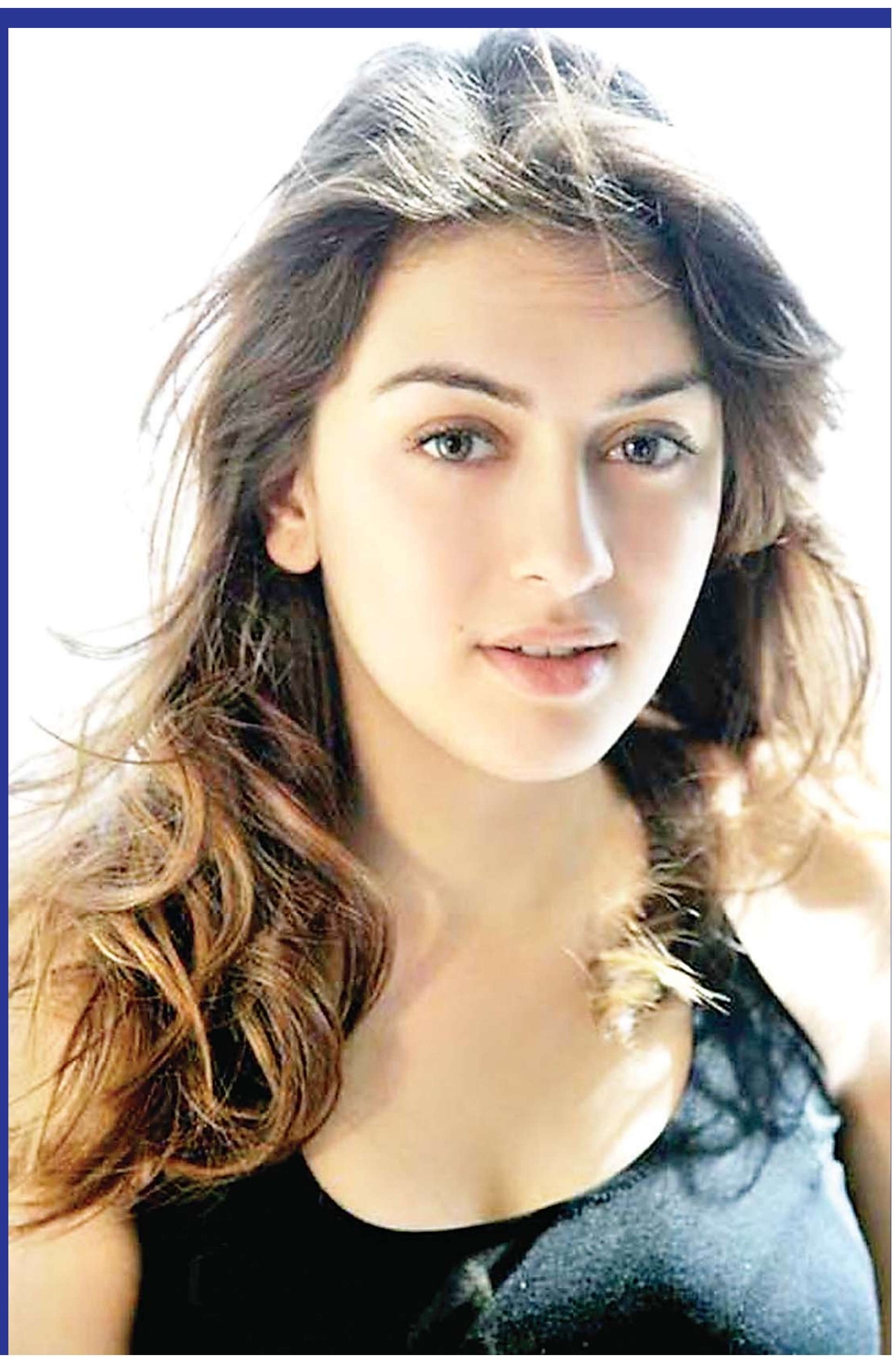

80 लाख में कान्स फिल्म फेस्टिवल एंट्री: उर्फी जावेद

उर्फी जावेद एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं, और इस बार वजह है उनका कान्स फिल्म फेस्टिवल को लेकर किया गया खुलासा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वहां शामिल होने के लिए भारी-भरकम रकम चुकानी पड़ सकती है। यह रकम कुछ चार-पांच लाख रुपये नहीं बल्कि 80 लाख रुपये है। उर्फी के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या कान्स जाने वाले सेलेब्स इतनी ही रकम अदा करके जाते हैं।

सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाने वाली उर्फी जावेद ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस बातचीत में कथित तौर पर एक शख्स उन्हें ऑफर देता नजर आया कि वह पैसे देकर उन्हें कान्स फिल्म फेस्टिवल में एंट्री दिलवा सकता है, कीमत थी करीब 80 लाख रुपये। इस स्क्रीनशॉट को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा, 80 लाख में कान्स? मैं इंडिया में ही ठीक हूं! क्या इतना क्रेज बढ़ गया है कि लोग इतनी बड़ी रकम देने को तैयार हैं? उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच बहस का विषय बन गया।

उर्फी के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक पुरानी चर्चा फिर से शुरू हो गई, क्या कुछ इंफ्लुएंसर्स सच में पैसे देकर कान्स जैसे बड़े इवेंट्स में शामिल होते हैं? पिछले कुछ सालों में कई डिजिटल क्रिएटर्स को इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखा गया है, जिससे यह सवाल बार-बार उठता रहा है। हालांकि, अब तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इस तरह की 'पेड एंट्री' असल में होती है। कई लोग मानते हैं कि ब्रांड कोलैबोरेशन और ऑफिशियल इनवाइट के जरिए ही ऐसे मौके मिलते हैं। लेकिन उर्फी के इस दावे ने शक को एक बार फिर हवा दे दी है।

इसी बीच उर्फी ने अपनी एक और इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी पर्सनल जर्नी को लेकर भी दिल की बात कही। उन्होंने माना कि उन्हें आज भी लगता है कि वह अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने लिखा कि वह आज भी खुद से पूछती हैं, मेरा समय कब आएगा? उर्फी ने यह भी शेयर किया कि उन्होंने हमेशा एक अलग और मुश्किल रास्ता चुना, जो आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें तारीफ सुनकर भी अजीब लगता था, क्योंकि वह ज्यादातर आलोचनाएं ही सुनने की आदी हो चुकी थीं।

काम की बात करें तो उर्फी जावेद इन दिनों रियलिटी शो स्ङ्क स्प्लिट्सविला ङ्ग6 में 'मिसचीफ मेकर' के रूप में नजर आ रही हैं। उनके साथ शो में निया शर्मा भी दिखाई दे रही हैं, और दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है।

रश्मिका मंदाना ने फैन्स को आत्म-प्रेम की याद दिलाई

एक ऐसी दुनिया में जो जीवन को व्यस्त बना रही है, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपने प्रशंसकों को आत्म-प्रेम के महत्व को याद दिलाने के लिए कुछ समय निकाला। रविवार को, रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने प्रशंसकों के लिए एक विचारशील संदेश साझा किया, साथ ही दो मनमोहक तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिसमें वह एक गुलाब पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों के साथ, अभिनेत्री ने एक कैप्शन भी जोड़ा, जिसमें सभी को खुद की सराहना करने और खुद के प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।आखिरी बार आपने खुद के लिए फूल कब खरीदे थे? बस एक विनम्र अनुस्मारक कि खुद की सराहना करें और अक्सर खुद को धन्यवाद दें... क्योंकि आप दुनिया के सभी प्यार और दयालुता के हकदार हैं, उन्होंने लिखा।वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका हाल ही में सलमान खान के साथ सिकंदर में नजर आई थीं।फिल्म का निर्देशन एआर मुरुगादॉस ने किया है, जो गजनी और थुप्पक्की जैसी तमिल और हिंदी ब्लॉकबस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं। साजिद नाडियाडवाला ने इस परियोजना का निर्माण किया, जिसने 2014 की ब्लॉकबस्टर किक के बाद सलमान खान के साथ फिर से काम किया। यह फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अभिनेत्री को छावा में भी देखा गया था, जिसमें अभिनेता विक्की कौशल थे और यह एक बड़ी हिट रही। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित लक्ष्मण उटेकर निर्देशित में अक्षय खन्ना ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। छावा विक्की कौशल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों- उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक, राजी, सैम बहादुर और जरा हटके जरा बचके को पीछे छोड़ दिया।

बक्सर स्टेशन पर आरपीएफ का ऑपरेशन 'यात्री सुरक्षा' सफल, मोबाइल चोर गिरफ्तार, सुरक्षा व्यवस्था और सख्त

बक्सर (संवाददाता)। बक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन 'यात्री सुरक्षा' अभियान के तहत शनिवार को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। इस अभियान के दौरान RPF टीम ने स्टेशन परिसर में सक्रिय एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यात्रियों में सुरक्षा को लेकर भरोसा और बढ़ा है।

जानकारी के अनुसार, निरीक्षक प्रभारी कुंदन कुमार के दिशा-निर्देशन में RPF की टीम लगातार स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और आसपास के क्षेत्रों में सघन निगरानी अभियान चला रही है। इसी क्रम में उप निरीक्षक विजेंद्र मुवाल अपनी टीम—आरक्षी दीपक कुमार, राहुल यादव और करन सिंह—के साथ नियमित गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर बनाए हुए थे।

शनिवार दोपहर गश्त के दौरान टीम की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी गतिविधियां असामान्य और संदिग्ध प्रतीत हो रही थीं। वह इधर-उधर घूमते हुए यात्रियों पर नजर रख रहा था, जिससे RPF टीम को उस पर शक हुआ। तत्परता दिखाते हुए टीम ने उसे तुरंत रोककर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम परदेसी माली, पिता अमर सिंह माली, निवासी थाना चौसा मुफस्सिल, जिला बक्सर बताया।

हालांकि उसके जवाब संतोषजनक नहीं थे, जिससे टीम का संदेह और गहरा गया। इसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद हुआ।

मोबाइल के संबंध में पूछने पर वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। सख्ती से पूछताछ करने पर अंततः उसने स्वीकार किया कि उसने यह मोबाइल बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री से चोरी किया था। आरोपी के इस कबूलनामे के बाद RPFटीम ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना की पुष्टि होने के बाद RPF ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी बक्सर के सुपुर्द कर दिया। जीआरपी द्वारा अब मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किसी बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ है या नहीं और इससे पहले उसने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है।

RPF अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन 'यात्री सुरक्षा' का मुख्य उद्देश्य रेलवे परिसरों में चोरी, उठाईगिरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसके तहत स्टेशन पर सीसीटीवी निगरानी, नियमित गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस तरह की लगातार कार्रवाई से स्टेशन परिसर में सक्रिय अपराधियों में भय का माहौल बना है। साथ ही यात्रियों को भी सतर्क रहने और अपने सामान की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने की सलाह दी गई है। RPF ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी इस तरह के विशेष अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेंगे, ताकि रेल यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और भयमुक्त वातावरण मिल सके।

बक्सर में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा

कूलरों में छिपाकर लाई जा रही 30 लाख की खेप जब्त, चालक-खलासी गिरफ्तार

बक्सर (संवाददाता)। जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में विभाग ने करीब 30 लाख रुपये मूल्य की भारी मात्रा में शराब जब्त की है। तस्करों ने शराब को चेकपोस्ट पर लगे स्कैनर से बचाने के लिए बेहद सुनियोजित तरीके से कुलरों के अंदर छिपाकर रखा था, लेकिन विभाग की सतर्कता और सूझबूझ के चलते उनका यह प्रयास विफल हो गया।

उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को पहले से ही इनपुट मिला था कि पंजाब से बिहार के लिए बड़े पैमाने पर अवैध शराब की खेप भेजी जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वीर कुंवर सिंह सेतु स्थित उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई। टीम को निर्देश दिया गया कि सभी संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। इसी क्रम में शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे एक ट्रक बिहार की सीमा में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। वाहन की गतिविधि और सूचना के आधार पर टीम को उस पर संदेह हुआ। चेकपोस्ट प्रभारी इंस्पेक्टर कुंदन कुमार के नेतृत्व में टीम ने ट्रक को रोककर उसकी जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के तहत ट्रक को स्कैनर से गुजारा गया, लेकिन इसमें शराब होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। इसके बावजूद टीम को शक बना रहा, क्योंकि सूचना बेहद सटीक मानी जा रही थी। इसके बाद अधिकारियों ने ट्रक की मैन्युअल जांच करने का फैसला लिया, जो आगे चलकर सही साबित हुआ। गहन तलाशी के दौरान जो खुलासा हुआ, उसने सभी को चौंका दिया। ट्रक में 55 छोटे-बड़े कुलर लोड किए गए थे, जिन्हें बेहद चालाकी से इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि उनके बीच में शराब की पेटियां छिपाई जा सकें। यह व्यवस्था इतनी तकनीकी ढंग से की गई थी कि स्कैनर भी इसे पकड़ नहीं सका।

जब टीम ने एक-एक कर कुलरों को हटाना शुरू किया, तो उनके बीच से शराब की पेटियां निकलने लगीं। कुल मिलाकर 449 पेटी शराब बरामद की गई। जब्त सामग्री में 300 पेटी बीयर शामिल है, जिसकी कुल मात्रा लगभग 3600 लीटर है, जबकि 149 पेटी विभिन्न ब्रांड की व्हिस्की बरामद हुई, जिसकी मात्रा करीब 1341 लीटर बताई जा रही है। इस तरह कुल 4941 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान मौके से ट्रक चालक और सहचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की पहचान मुकेश कुमार और सुबोध कुमार के रूप में हुई है, जो जमुई जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि यह शराब पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ से लोड की गई थी और इसे बिहार के जमुई जिले तक पहुंचाना था।

उत्पाद विभाग ने ट्रक, शराब की पूरी खेप और 55 कुलरों को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शराब तस्कर लगातार नए-नए तरीके अपनाकर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विभाग भी उतनी ही सतर्कता और तकनीकी सहयोग के साथ इन पर नजर बनाए हुए है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तस्कर अब पारंपरिक तरीकों के अलावा नए छुपाव तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए विभाग को और अधिक आधुनिक रणनीतियां अपनानी पड़ रही हैं।

उत्पाद विभाग ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी को कहीं भी अवैध शराब के भंडारण, बिक्री या तस्करी की जानकारी मिलती है, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और इस तरह के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में चेकपोस्ट और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और भी बढ़ाई जाएगी, ताकि तस्करी के ऐसे प्रयासों को समय रहते नाकाम किया जा सके।

10वीं टॉपर्स का भव्य सम्मान समारोह

बक्सर (संवाददाता)। चुरामनपुर स्थित ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के सम्मान एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए एक भव्य आशीर्वाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का माहौल उत्साह, खुशी और गर्व से भरा रहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक धीरज पांडेय, उप प्रबंधक धर्मेंद्र पांडेय, प्रधानाचार्या सोनिका, राहुल जायसवाल समेत सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया गया।

बक्सर में इंसानियत शर्मसार

मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार

बक्सर (संवाददाता)।

जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव से एक बेहद संवेदनशील और शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक 35 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला उजागर हुआ है। घटना के सामने आने के बाद गांव सहित पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है, वहीं पीड़िता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता तियरा गांव की निवासी है और उसकी शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी। लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण वह अपने ससुराल में नहीं रह पा रही थी और फिलहाल अपने मायके में ही रह रही थी। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए गांव के ही दो युवकों ने उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।

परिजनों को घटना की जानकारी तब हुई जब उन्हें पीड़िता की स्थिति पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने उससे पूछताछ की और मामला सामने आते ही तुरंत राजपुर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज की और त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। राजपुर थानाध्यक्ष निवास कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित छापेमारी अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्येंद्र राम और विजय राम के रूप में की गई है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस बीच, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, ताकि घटना से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें और अदालत में केस को मजबूत आधार पर प्रस्तुत किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ लिया जा रहा है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से पीड़िता और उसके परिवार को हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी और मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

अग्नि सुरक्षा सप्ताह में जागरूकता अभियान तेज

मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण से लोगों को किया जा रहा सतर्क

बक्सर (संवाददाता)। जिले में 14 से 20 अप्रैल 2026 तक मनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष सिंह के निर्देशानुसार यह अभियान पूरे जिले में सक्रिय रूप से संचालित हो रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना और आपात स्थिति में सही प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करना है।

इस अभियान के तहत अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी सुनंदा कुमारी के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग की टीम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। गांवों से लेकर शहरी वार्डों तक लोगों को सीधे जोड़कर उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आग लगने की स्थिति में समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के पांचवें दिन शनिवार, 18 अप्रैल को जिले के कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़की सारिमपुर में जीविका दीदियों के साथ बैठक कर उन्हें घरेलू और सामुदायिक स्तर पर आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास कराया गया, जिससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा।

वार्ड नंबर 38 में वार्ड पार्षद के सहयोग से बैठक और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) के सही उपयोग की जानकारी दी और लोगों को इसे खुद इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी दिया। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती स्तर पर आग को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है।

इसके अलावा जिले के विभिन्न हिस्सों में बैनर और होर्डिंग लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और प्रमुख चौक-चौराहों पर लगाए गए संदेशों के माध्यम से आमजन को आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। अभियान के तहत चौसा क्षेत्र में डायल 112 और अग्निशमन सेवा के आपातकालीन नंबर 101 की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें, ताकि समय पर सहायता मिल सके।

ग्राम पवनी (वार्ड नंबर 6) में जीविका समूह की महिलाओं के साथ बैठक कर उन्हें घरेलू गैस, बिजली के उपकरणों और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में बताया गया। वहीं वार्ड नंबर 7 में जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

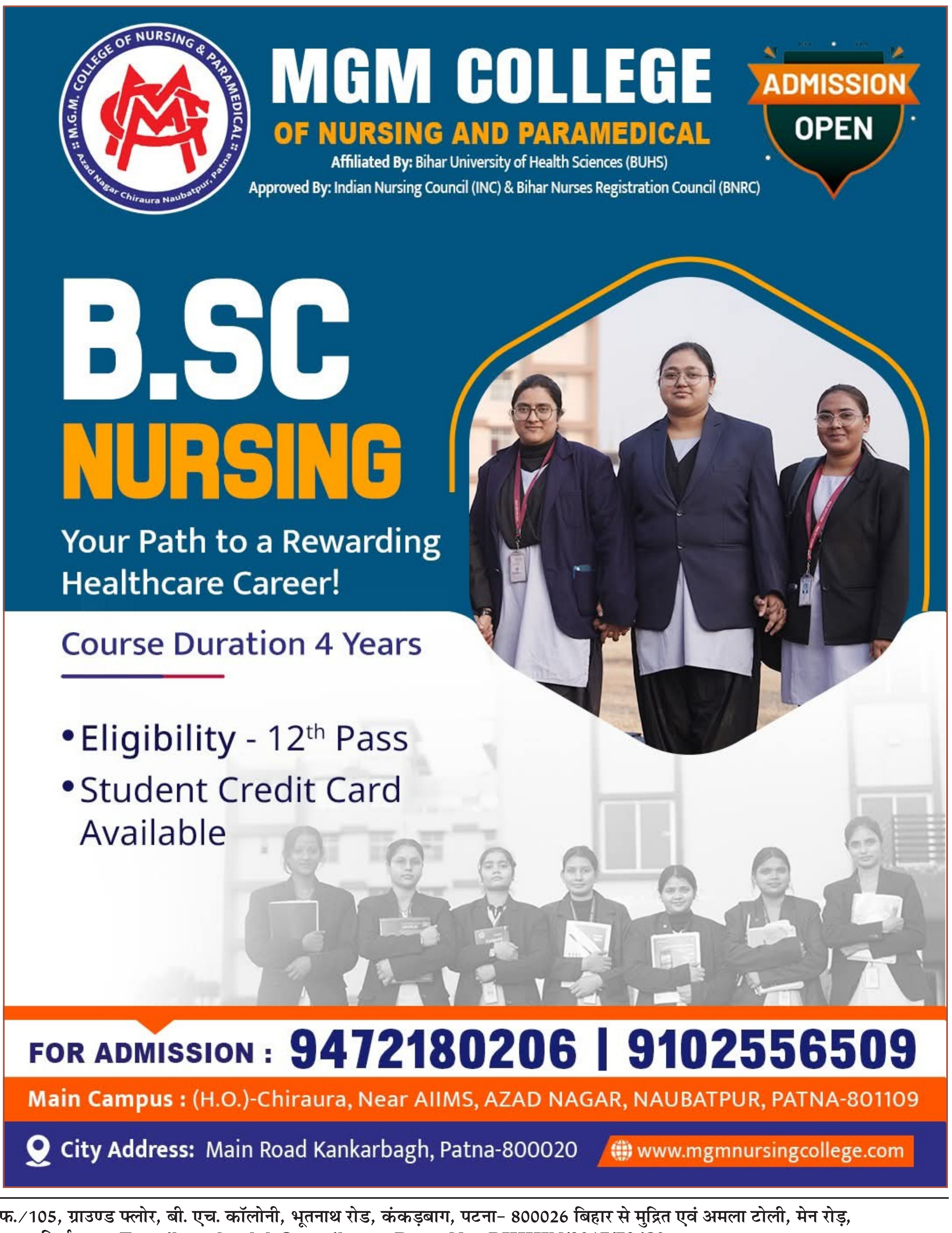

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मतिउर्रहमान द्वारा अजीमाबाद प्रिंटर्स, आर. सी. एफ./105, ग्राउण्ड फ्लोर, बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना- 800026 बिहार से मुद्रित एवं अमला टोली, मेन रोड़, बक्सर -802101, बिहार से प्रकाशित, संपादक- मतिउर्रहमान, E-mail:- qalamlok@gmail.com, Regn. No. BIHHIN/2017/72480